



Centre for  
CIVIL  
SOCIETY

SOCIAL CHANGE THROUGH PUBLIC POLICY

# अन्नदाता से कृषि-उद्यमी तक

भारतीय कृषि में सुधार के लिए सुझाव पुस्तिका



# अन्नदाता से कृषि-उद्यमी तक

भारतीय कृषि में सुधार के लिए सुझाव पुस्तिका

भुवना आनंद, रितिका शाह और सुधांशु नीमा

नई दिल्ली, भारत

अगस्त 2020



SOCIAL CHANGE THROUGH PUBLIC POLICY

---

\* सधन्यवाद अर्जुन कृष्णन

कॉपीराइट ©2020

प्रथम प्रकाशन 2020

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा

कवर डिजाइन: रवि कुमार यादव,

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी

लेखक: भुवना आनंद, रितिका शाह और सुधांशु नीमा

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी

कृपया कार्य को नि अनुसार उद्धृत करें:

भुवना आनंद, रितिका शाह और सुधांशु नीमा. 2020. अ दाता से कृषि-उद्यमी तक.

भारतीय कृषि में सुधार के लिए सुझाव पुस्तिका . सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी

अधिक जानकार और अ अनुरोधों के लिए, यहां लिखें:

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी

ए-69 हौजखास

नई दिल्ली 110016

फ़ोन- +91 11 2653 7456 | ईमेल: [ccs@ccs.in](mailto:ccs@ccs.in) | वेबसाइट: [www.ccs.in](http://www.ccs.in)

ISBN: 978-81-87984-49-8

## सामग्री

### कार्य सारांश 5

#### 1.परिचय: संकटग्रस्त क्षेत्र 6

भारत में किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा, किसान काफी गरीब और कर्जग्रस्त .....	7
उत्पादकता कम, निवेश लागत ज़्यादा, बाजार से लाभ का अभाव .....	8
सरकार हर जगह है, शासन कहीं नहीं है .....	9

#### 2.निदान: बाजारों से छेड़छाड़ को लेकर सावधान करने की कहानी 11

कौन सी फसल उगाएं, कितना निवेश करें और क्या जोखिम उठाएं इसे लेकर हस्तक्षेप .....	11
कितना निवेश करें और किन निवेश वस्तुओं का इस्तेमाल करें इसे लेकर हस्तक्षेप .....	12
कितना भंडार करें, और कब, कहाँ एवं किसे बेचे इसे लेकर हस्तक्षेप .....	13

#### 3. सुधार: कृषि में लाइसेंस-नियंत्रित-सब्सिडी राज का अंत करें 14

1 भूमि स्वामित्व, बिक्री, काश्तकारी और इस्तेमाल पर लगी रोक हटाएँ .....	14
2 घरेलू हाजिर उपभोक्ता बाजारों का उदारीकरण करें .....	18
3 वस्तु वायदा बाजारों को प्रोत्साहन दें .....	23
4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगी रोक हटाएँ.....	25
5 सरकारी खरीद की कीमत तय करना बंद करें और उसे तर्कसंगत बनाएँ .....	29
6 निवेश सब्सिडी से प्रत्यक्ष हस्तांतरण की ओर बढ़ें .....	32
7 ऋण बाजारों में हस्तक्षेप करने की इच्छा से बचें .....	35
8 आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलों के विनियमन के लिए एकल विंडो मंच स्थापित करें.....	38

#### 4. निष्कर्ष: अन्नदाता से उद्यमी.....41

#### संदर्भ ग्रंथ सूची 43

## कार्य सारांश

सरकार और समाज ने हमेशा से खेती को देश के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के एक साधन के रूप में देखा है। किसानों को अन्नदाता माना जाता है, न कि वैध उद्यमी जो कृषि का व्यवसाय करते हैं। 1991 के उदारीकरण से कृषि क्षेत्र पूरी तरह अछूता रहा। कुख्यात लाइसेंस, परमिट और कोटा राज किसानों को सम्मानजनक तरीके से आजीविका कमाने से आज भी रोक रहे हैं। किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन सभी सफल नहीं हुईं। उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं के व्यवस्थागत हल की तलाश करने के बजाय, केंद्र और राज्य सरकारें अल्पकालिक, लेकिन वोट जीतने वाले तरीकों का इस्तेमाल करती हैं।

दशकों के नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद, ज़्यादातर भारतीय किसानों की आय में वृद्धि नहीं हुई है, न ही वे कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर पाए हैं। वे किसान जिनके पास छोटी या सीमांत जोत हैं और जो कुल किसानों का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं, खुद को ऋणग्रस्तता, कृषि निवेश (इनपुट) में विकल्प की कमी और अविकसित गोदाम एवं प्रसंस्करण सुविधाओं का शिकार पाते हैं। हर कृषि चक्र में कई किसान आंदोलन होते हैं, जिसके बाद टॉप-अप सब्सिडी, ऋण माफी या नई किसान सहायता योजनाओं के रूप में और अल्पकालीन समाधान दे दिए जाते हैं।

एक के बाद एक सरकारों ने कृषि निवेश वस्तुओं की कीमत पर सब्सिडी देकर और उत्पादन के लिए उच्च समर्थन मूल्य की पेशकश करके किसानों की मदद करने की कोशिश की है। निवेश (इनपुट) कीमतों को कम करने के लिए सरकारें बीज, उर्वरक, बिजली, पानी, कृषि मशीन और अनुसंधान एवं विकास के लिए कई सब्सिडी प्रदान करती हैं। उत्पादन की कीमत बढ़ाने के उपायों के तहत, केंद्र और राज्य सरकारें कई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद करती हैं। इसके साथ ही, नीतिगत उपायों की वजह से भारत की दो-तिहाई से ज़्यादा आबादी को भारी सब्सिडी वाले, सस्ते अनाज मिलते हैं।

सुझाव पुस्तिका यह दलील देती है कि इन नीतिगत हस्तक्षेपों ने किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इतना ही नहीं, भारत उन कुछ देशों में से एक है जहाँ किसानों को नकारात्मक सब्सिडी मिलती है और उन्हें शुद्ध घाटा होता है। ये नीतियां इस बात को नज़रअंदाज़ करती हैं कि इस क्षेत्र में संकट ज़्यादातर किसानों का कृषि में कम या कोई नियंत्रण नहीं होने का परिणाम है, किसानों का नियंत्रण मिट्टी की जोताई तक सीमित है।

भारतीय कृषि नीतियां बाजार प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने की चेतावनी देती हैं। सरकार उत्पादन और बिक्री प्रक्रिया के हर कदम पर फैसलों में हस्तक्षेप करती है। नीतियां किसानों को बताती हैं कि क्या उगाना है, कैसे उगाना है, कितना निवेश करना है, कितना भंडार करना है, कब, कहाँ और किसे बेचना है तथा कितने में बेचना है। एक रूप में देखे जाने पर कहा जा सकता है कि नीतिगत संरचना ने कीमतों द्वारा निर्भाई गई सांकेतिक भूमिका को नष्ट कर दिया है, और इसके लिए कोई भी बेहतर नहीं है।

वित्त मंत्री ने जुलाई 2019 में अपने पहले बजट भाषण में व्यापार करने में आसानी के दायरे का विस्तार करते हुए उसमें ग्रामीण उद्यमों को शामिल करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि "व्यापार करने में आसानी और जीने में आसानी, दोनों ही किसानों पर भी लागू होने चाहिए।" बदकिस्मती से, भारत में राजनीतिक और सामाजिक विमर्श अभी भी किसान को एक उद्यमी के रूप में नहीं देखता है जो जोखिम लेता है, बाजार का विश्लेषण करता है और कृषि उपज के उत्पादन, विपणन एवं बिक्री में शामिल होता है।

इस पृष्ठभूमि में, इस योजना पुस्तिका का उद्देश्य तीन लक्ष्य प्राप्त करना है:

- एक उद्यम के रूप में कृषि की कल्पना करना, और किसानों को 'कृषि उद्यमी' के तौर पर पेश करना
- समृद्ध अध्ययन और रिपोर्ट से महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल करना; और
- इस क्षेत्र में आवश्यक सुधारों की पूरी श्रेणी की रूपरेखा तैयार करना।

नीतिगत दृष्टिकोण व्यापक रूप में "पहले लेन-देन" के मिथक का बंधक बना हुआ है, यह धारणा जितनी पुरानी है, उतनी ही खतरनाक भी है। सुझाव पुस्तिका का दृष्टिकोण इस धारणा को दरकिनार करने और इस क्षेत्र को किसी अन्य क्षेत्र की ही तरह देखना है। किसान अलग-थलग इकाई नहीं हैं, बल्कि उद्यमी हैं जो बाजार की प्रक्रिया में शामिल हैं और वे कीमतों और अपने प्रतिस्पर्धियों एवं खरीदारों के कार्यों से संकेतों को अवशोषित करते हुए, किस बीज का उपयोग करना है, इसपर और बिक्री के लिए भंडारण में मध्यस्थता की क्षमता पर व्यावसायिक निर्णय लेते हैं। यह पुस्तिका कृषि क्षेत्र में ज़रूरी आठ विशिष्ट सुधारों को सूचीबद्ध करती है ताकि हमारे कृषि उद्यमी उत्पादन और बिक्री के लिए स्वतंत्र हो सकें। से सुधार अदूरदर्शी भूमि नियमों, प्रतिगामी इनपुट सब्सिडी और नियंत्रण व्यवस्था, तथा हाजिर, वायदा एवं ऋण बाजारों की बेड़ियों को काटते हैं। पुस्तिका मुख्य रूप से उन बुरी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है जिन्हें निरस्त करने या बदलने की ज़रूरत है, यह उन चीजों पर कम ध्यान देती है जिसे सरकार को ज़्यादा करने की ज़रूरत है।

## 1. परिचय: संकटग्रस्त क्षेत्र

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। यह गेहूँ, चावल, दाल, गन्ना और कपास के शीर्ष उत्पादकों में से एक है; दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, और फलों एवं सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (देशपांडे 2017) है। 2019-20 में, भारत में 29.2 करोड़ टन खाद्यान्न (पत्र सूचना कार्यालय 2020) सहित 72.5 करोड़ टन से अधिक कृषि उपज के उत्पादन की उम्मीद थी।

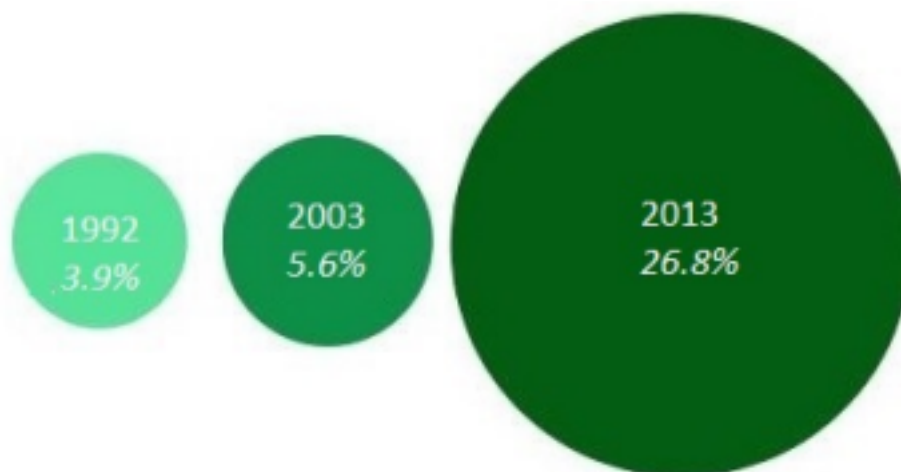
हालांकि क्षेत्र में सब कुछ सही नहीं है। पिछले 15 वर्षों में कृषि का विकास काफी अस्थिर रहा है, 2005-06 में 5.8 प्रतिशत से लेकर 2009-10 में 0.4 प्रतिशत और 2014-15 में -0.2 प्रतिशत (देशपांडे 2017)। 2018 में, कृषि के लिए जीडीपी डिफ्लेटर (अपस्फीतिकारक) कई वर्षों में पहली बार नकारात्मक हो गया (घोष 2018)। दूसरे शब्दों में कहें तो पहले की तुलना में किसानों की आय कम हो गयी। 2016 में, देश के कुल कार्यबल का 59% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर था, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान केवल 23% था (खाद्य एवं कृषि संगठन 2019)। इसके अलावा उत्पादन संसाधन गहन, अनाज केंद्रित और क्षेत्रीय रूप से पक्षपातपूर्ण है। भारतीय कृषि के संसाधन गहन तरीकों ने स्थिरता संबंधी चिंताओं को जन्म दिया है। इनमें देश के जल संसाधनों पर दबाव, मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण शामिल हैं (खाद्य एवं कृषि संगठन 2019)।

## भारत में किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा, किसान काफी गरीब और कर्ज़ग्रस्त

भारतीय कृषि संकट में है और ऐसा कुछ समय से है। हर तीन भारतीय किसानों में से एक गरीबी रेखा से नीचे है<sup>1</sup>। लगभग 85 प्रतिशत किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है (पत्र सूचना कार्यालय 2019); इससे उनके लिए अपने कामकाज को बढ़ाना और अपनी आय में वृद्धि करना असंभव हो जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के अनुसार, भारत में कृषि क्षेत्र केवल 14 करोड़ लोगों की आजीविका संबंधी ज़रूरत पूरी कर सकता है (श्रीकांत 2017)। लगभग 14.5 करोड़ भूमिहीन मजदूर हैं जो ज़्यादातर राज्यों में किसान की परिभाषा के अंतर्गत भी नहीं आते हैं। उन्हें सरकार से मदद नहीं मिलती है और वे खेतों पर मौसमी रोजगार के सहारे जीते हैं।

वर्ष 2013 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने पाया कि एक किसान परिवार की औसत मासिक आय मात्र महज 6,426 रुपए है (एनएसएस 2013)। इसमें से 6,223 रुपये मासिक खपत के लिए थे यानी एक छोटे किसान की मासिक बचत केवल 200 रुपये थी। 2018 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 2015-16 में एक औसत कृषि परिवार के लिए 8,931 रुपये की आय का अनुमान लगाया था। वहीं हर कृषि परिवार पर औसतन 1,07,083 रुपए का कर्ज़ था (नाबार्ड 2018ए)। ग्रामीण क्षेत्रों में गिरती खपत भी कम आय और ऋणग्रस्तता की इस कहानी की पुष्टि करती है। 2019 में आयी मीडिया की खबरों में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के एक अप्रकाशित सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा गया है कि जुलाई 2017 और जून 2018 के बीच ग्रामीण भारत में खर्च 8.8 प्रतिशत कम हो गया।

नीति आयोग का अनुमान है कि किसानों की आय दोगुनी होने में 22 साल (1993 से 2015) लगे (दलवई 2017)। जैसे-जैसे कर्ज़ बढ़ता है, वैसे-वैसे चक्र को बनाए रखने के लिए खेत के संचालन की लागत भी बढ़ती है। कर्ज़ का यह जाल छोटे खेतों को पंगु बना सकता है। दूसरे शब्दों में, औसत भारतीय किसान बेहद गरीब हैं और कर्ज़दार हैं।



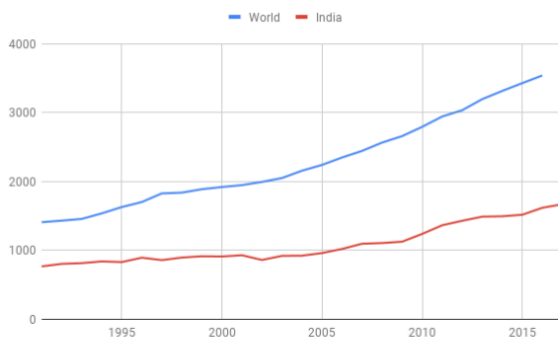
चित्र 1: किसान परिवारों के बीच औसत ऋण और संपत्ति अनुपात (%)

स्रोत: एनएसएस 1992, 2003, 2013

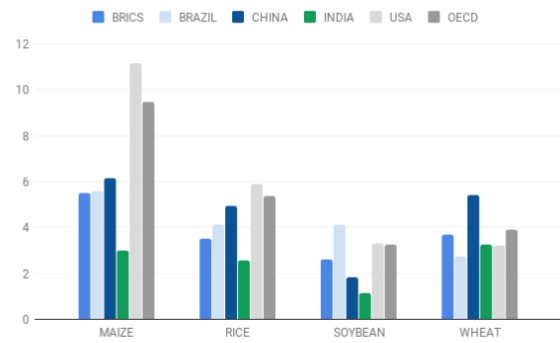
<sup>1</sup> ग्रामीण इलाकों में 328 रुपए प्रति व्यक्ति और शहरी इलाकों में 455 रुपए प्रति व्यक्ति

## उत्पादकता कम है, निवेश लागत ज़्यादा है, बाजार से मिलने वाला लाभ का अभाव है

भारत में खेत प्रतियोगी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में प्रति हेक्टेयर कम उपज देते हैं। 1960 के दशक की हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले उत्पादकता संबंधी शुरुआती समस्याओं का हल करने में मदद की। यह चलन जारी नहीं रहा। प्रति मजदूर कृषि संवर्धित मूल्य 1991 में 769 डॉलर था और 2017 तक यह बढ़कर केवल 1,621 डॉलर हुआ। इसमें 26 वर्षों में 110.7% की वृद्धि हुई। इसी समय सीमा में, वैश्विक वृद्धि 151% थी जो 1,411 डॉलर से बढ़कर 3,542 डॉलर हो गयी (विश्व बैंक 2020)। उदाहरण के तौर पर चावल और गेहूँ के लिए भारत की उपज दर -प्रति हेक्टेयर उत्पादित टन- को लें। चावल के मामले में भारत में भूमि उत्पादकता चीन की लगभग आधी और अमेरिका की एक तिहाई है (देशपांडे 2017)। 2019 में, भारत की प्रति हेक्टेयर गेहूँ की उपज 3.2 टन और चावल की उपज 2.6 टन थी, जबकि यूरोपीय संघ की गेहूँ और चावल की प्रति हेक्टेयर उपज क्रमशः 5.5 और 4.0 टन थी (ओईसीडी 2020)।



क. मजदूरों द्वारा संवर्धित कृषि मूल्य  
स्रोत: विश्व बैंक 2020

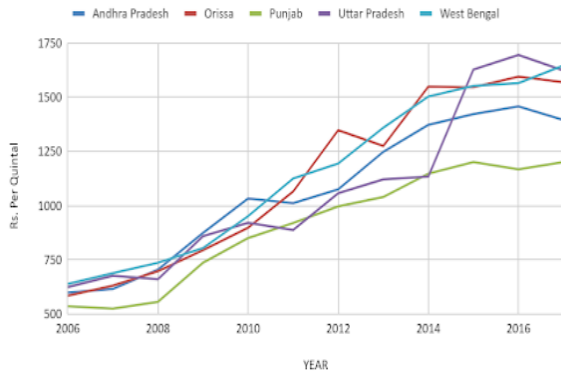


ख. चुनिंदा फसलों की पैदावार  
स्रोत: ओईसीडी 2020

चित्र 2: भारतीय कृषि के लिए उत्पादकता के संकेतक

भारत में खेतों का औसत आकार, 1.08 हेक्टेयर, ज़्यादातर किसानों के लिए मशीनों में निवेश करना लाभहीन बना देता है (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2019ए)। भारतीय किसानों को अपेक्षाकृत ज़्यादा और बढ़ती निवेश लागत का भी सामना करना पड़ता है। दलवाई समिति (2017) की रिपोर्ट में पाया गया कि जहाँ किसानों द्वारा प्रति हेक्टेयर निकाले जाने वाले कृषि मूल्य में वृद्धि हुई है, कम से कम 2010 तक, इनपुट लागत में कमोबेश ज़्यादा वृद्धि हुई है। जैसा कि चित्र 3ए में देखा गया है, खेती की कुल लागत (रुपये प्रति क्विंटल) पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2015) में 2006 से 2017 तक तेजी से बढ़ी है।

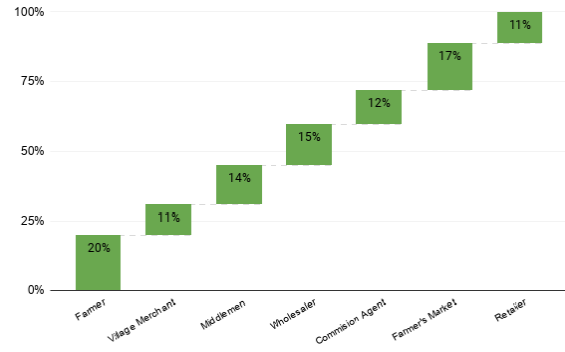




क. धान की खेती के खर्च में वृद्धि

मूल्य निर्धारण

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2015



ख. आंध्र प्रदेश में फल एवं सब्जी मूल्य श्रृंखला में

स्रोत: मुखर्जी और अन्य 2013

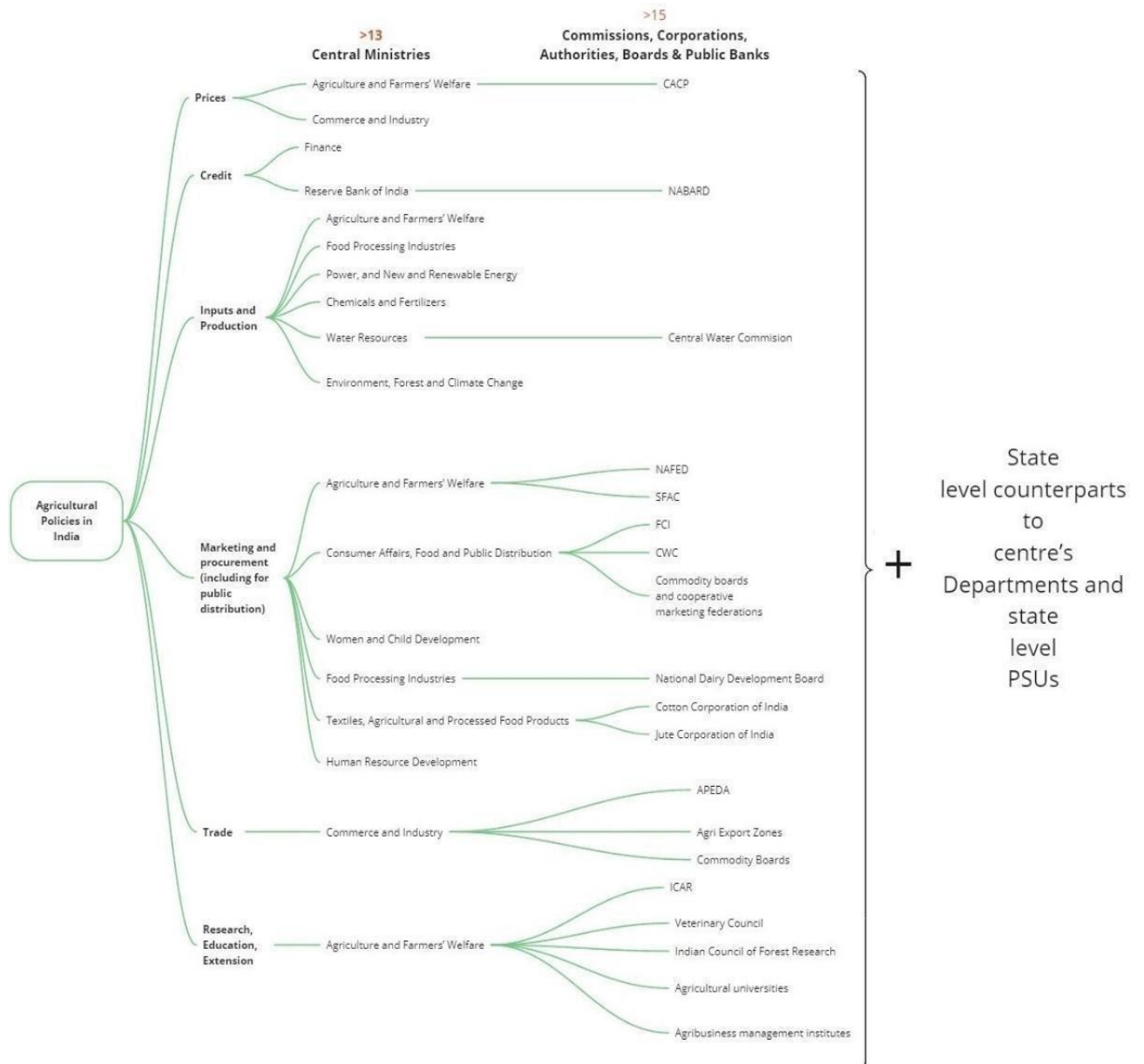
चित्र 3: भारतीय कृषि के लिए खर्च और लाभ के संकेतक

देश के 16 राज्यों की कृषि मंडियों में किए गए भारतीय रिज़र्व बैंक (2019) के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि किसानों को 14 खाद्य पदार्थों के अंतिम खुदरा मूल्य का 28 से 78 प्रतिशत हिस्सा ही प्राप्त होता है। जहाँ 62% किसानों का मानना है कि वे उत्पादन की लागत को पूरा करने में सक्षम थे, यह अनुपात खराब होने वाली वस्तुओं के लिहाज से कम हो जाता है। सभी स्तरों पर लागतें हैं। किसान मंडी और पैकिंग शुल्क का भुगतान करते हैं, व्यापारी दुकान, श्रम, परिवहन और भंडारण के लिए भुगतान करते हैं और खुदरा विक्रेता कर, किराया और श्रम लागत का भुगतान करते हैं।

## सरकार हर जगह है, शासन कहीं नहीं है

भारत में कृषि नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कई मंत्रालय, विभाग, बोर्ड और संस्थान शामिल हैं (अरोड़ा 2013)। संविधान राज्य सरकारों के दायरे में कृषि और संबंधित विषयों को सूचीबद्ध करता है। जहाँ भारत सरकार का कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय कृषि नीति का प्राथमिक चालक बना हुआ है, केंद्रीय स्तर पर कम से कम 12 अन्य मंत्रालय कृषि और खाद्य नीति (ओईसीडी 2018) के पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार नीति निर्देश प्रदान करती है जबकि इन नीतियों और दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन और प्रशासन राज्य सरकारों के दायरे में है। नीति कार्यान्वयन के लिए धन का आवंटन बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, 15 से ज़्यादा अलग-अलग केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, विशेष रुचि विपणन संघ और कमोडिटी बोर्ड निर्णय श्रृंखला का हिस्सा हैं।

भारत सरकार और राज्य सरकारें कृषि में पूंजी, ऋण, इनपुट, मूल्य, प्रौद्योगिकी, बाजार पहुंच और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए मिशन, योजनाओं और अन्य का इस्तेमाल करती हैं। ये कार्यक्रम कार्यकारी नीति उपाय हैं जिन्हें कानूनी रूप नहीं दिया गया है। ये कार्यकारी नीति उपाय सत्तारूढ़ सरकारों को कृषि पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने और राजनीतिक हितों को किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को खत्म करने में मदद करते हैं।



चित्र 4: कृषि नीतियां और उनसे जुड़े मंत्रालय<sup>2</sup>

स्रोत: ओईसीडी 2018 और अरोड़ा 2013

<sup>2</sup> आईसीएआर = भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, एपीडा = कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, सीडब्ल्यूसी = केंद्रीय भंडारण निगम, एफसीआई = भारतीय खाद्य निगम, एसएफएसी = लघु किसान कृषि-व्यापार संघ, नैफेड = भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नाबार्ड = राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सीएसीपी = कृषि लागत और मूल्य आयोग।

## 2. निदान: बाजारों से छेड़छाड़ को लेकर सावधान करने की कहानी

देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने और वैश्विक व्यापार में कृषि के महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, किसानों को स्वतंत्र और तर्कसंगत आर्थिक भागीदार नहीं माना जाता है। उन्हें अन्य वस्तुओं के उत्पादकों की तरह बाजार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कृषि क्षेत्र के हर पहलू पर शुरू से अंत तक काफी सरकारी नियंत्रण है। किसानों को विशेष रूप से, 'पहले लेनदेन' की अवधारणा का बंधक बना लिया जाता है, जहाँ किसानों की उपज की पहली बिक्री केवल सरकारी मंडियों में ही बेची जा सकती है।

यह पुराने समय की नीति को ढो रहे हैं जब खाद्य सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय थी और किसानों का शोषण आम बात थी। स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने स्वतंत्रता से ठीक पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए उपायों को जारी रखा। कृषि उत्पादों के मामले में, नियंत्रण में लगभग सभी राज्यों में खुले बाजार की खरीद से लेकर राशनिंग तक फसलों की दुलाई शामिल थी (अमृतांशु2017)। आजादी के बाद के दशकों में कृषि पर नियंत्रण बढ़ता चला गया। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में सरकार की नीति उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए खाद्य कीमतों को कम रखने के पक्ष में झुकी (लिप्टन1975)। कृषि और खाद्य वस्तुओं में मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने के लिए सरकार की प्रतिक्रियाओं में निर्यात प्रतिबंध, मूल्य निर्धारण एवं परिवहन, भंडारण और अंतर-राज्य दुलाई पर प्रतिबंध शामिल हैं।



चित्र 5: भारत में कृषि नीति के उद्देश्य

स्रोत: ओईसीडी 2018, पेज. 153

## कौन सी फसल उगाएं, कितना निवेश करें और क्या जोखिम उठाएं इसे लेकर हस्तक्षेप

1965 तक, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कर दी थी। आयोग ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा जाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा पुनर्वितरित किए जाने के लिए प्रमुख कृषि वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कीं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के समन्वय से, बड़ी मात्रा में गेहूँ, चावल और कुछ अन्य वस्तुओं की खरीद

करती है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और विभिन्न राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अनाज की खरीद के लिए जिम्मेदार हैं। खरीदे गए अनाज का उपयोग बफर स्टॉक के रूप में और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किया जाता है, जिसके तहत सरकार गरीबों को रियायती कीमतों पर गेहूँ और चावल बेचती है।

केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर कीमतें तय करती है। अलग-अलग राज्यों को भी एमएसपी में बोनस जोड़ने की अनुमति है, जो कि ज़्यादातर राज्य नियमित रूप से करते हैं। 2009 में कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के संदर्भ की शर्तों के अनुसार एमएसपी का निर्धारण मांग और आपूर्ति, उत्पादन लागत, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में कीमतों के रुझान, अंतर-फसल मूल्य समानता; कृषि और गैर-कृषि के बीच व्यापार की शर्तों; उत्पादन की लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत का लाभ और खरीदारों पर संभावित प्रभावों के आधार पर किया जाता है। राजनीति, निश्चित रूप से, एमएसपी तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें आम तौर पर चुनाव से पहले एमएसपी में वृद्धि की घोषणा करती हैं (भारद्वाज और जाधव 2018)।

केंद्र और राज्य इन अनाजों को किसानों से विकेंद्रीकृत खरीद योजना या केंद्रीय खरीद योजना के माध्यम से खरीदते हैं। किसानों को इस अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जाती है, और उन्हें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह एमएसपी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल किए गए लोगों द्वारा भुगतान की गई कीमत से कहीं अधिक है। उदाहरण के लिए, धान की एमएसपी 2019-2020 में सिर्फ 18.15 रुपये प्रति किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा थी (एमएसपी 2019)। इस धान को दो रुपये प्रति किलो की दर से जन वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने से पहले इसे कूटना और चावल में बदलना ज़रूरी होता है।

एमएसपी पर सरकार द्वारा कृत्रिम रूप से निर्धारित मूल्य और खरीद, बुवाई के फैसले को प्रभावित करती हैं जिसकी वजह से चुनिंदा संसाधन गहन और अनाज केंद्रित फसलों का अत्यधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा, फसल-निर्देशित सब्सिडी भी बाजारों के कामकाज पर असर डालती है। उदाहरण के लिए, सरकार अकसर गन्ना किसानों को निर्यात और ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करती है।

## कितना निवेश करें और किन निवेश वस्तुओं का इस्तेमाल करें इसे लेकर हस्तक्षेप

भारत उर्वरक, बिजली, पानी, बीज, मशीनों, बीमा और ऋण सहित कृषि आदानों पर भी सब्सिडी देता है। कुछ वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के साथ, हाजिर बाजार में कीमतों का पता लगाना लगभग असंभव है। व्यापार की आवश्यकता के तौर पर लागत में कमी करीब-करीब अप्रासंगिक बन जाती है। बुआई के फैसलों पर प्रभाव ने अन्य अनपेक्षित परिणामों पर भी असर डाला है। इनपुट सब्सिडी ने फसल के विकल्पों और खेती के तरीकों पर भी असर डाला है। जहाँ सब्सिडी किसानों की आय को सुरक्षित करने में मदद करती है, वे कम कृषि उत्पादकता और छोटी जोत के संरचनात्मक मुद्दों को हल नहीं करती हैं। अत्यधिक श्रम की चुनौतियों का हल कृषि इनपुट सब्सिडी से नहीं किया जा सकता (रामस्वामी 2019)।

देश में बिजली की कुल खपत में कृषि उद्योग का लगभग 20% हिस्सा है (एमओएसपीआई 2018, पेज.39)। कई राज्य किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करते हैं और कृषि के लिए दिए जाने वाले ज़्यादातर कनेक्शन के लिए बिजली के मीटर की जांच नहीं की जाती है। मुफ्त या कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराने के फैसले ने आश्चर्यजनक रूप से किसानों के व्यवहार को प्रभावित किया है। ज़्यादातर बिजली का इस्तेमाल भूजल निकालने के लिए किया जाता है, जिससे 60% से अधिक सिंचाई की जाती है (एमओएसपीआई 2017)। एफएओ का अनुमान है कि भारत 251 अरब क्यूबिक मीटर पानी के

साथ दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, यह चीन द्वारा उपयोग किए जाने वाले भूजल के दोगुने से भी ज़्यादा है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण (2016) का अनुमान है कि देश में बचे जाने कुल यूरिया का लगभग 40% हिस्सा बांग्लादेश और नेपाल में किसानों को बिक्री के लिए तस्करी कर भेजा जाता है। इससे यूरिया की आपूर्ति और राशनिंग में कमी हो गई और आधे से ज़्यादा किसान यूरिया को काला बाजार में खुदरा मूल्य से अधिक कीमतों पर खरीदते हैं।

## कितना भंडार करें, और कब, कहाँ एवं किसे बेचे इसे लेकर हस्तक्षेप

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 द्वितीय विश्व युद्ध, विभाजन और भोजन की कमी के बाद उपभोक्ताओं को 'बेईमान' व्यापारियों द्वारा शोषण से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था (चिकरमाने2018)। यह अधिनियम सरकार को आवश्यक समझे जाने वाले सामानों के भंडारण की सीमा तय करने और उनकी ढुलाई को प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाता है (द टेलीग्राफ2019)। अधिनियम सरकार को 'आवश्यक' समझी जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन, आपूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। वस्तुओं की सात व्यापक श्रेणियाँ हैं जिन्हें "खाद्य तिलहन और तेल सहित खाद्य पदार्थों" को शामिल करने के लिए ज़रूरी समझा जा सकता है। यह अधिनियम कृषि में निजी निवेश और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को गंभीर रूप से सीमित करता है। जैसा कि सरकार किसी भी समय किसी सामान को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है और उसके नियंत्रण के लिए कई आदेश पारित कर सकती है, उद्यमी इसे भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन सुविधाओं में निवेश करने के लिहाज से बहुत जोखिम भरा मानते हैं।

इसके अलावा, कई वर्षों तक भारत के ज़्यादातर राज्यों में कृषि विपणन कानूनों के माध्यम से कृषि वस्तुओं की बिक्री के पहले बिंदु के लिए सरकार द्वारा विनियमित एकाधिकार था। मंडियों की स्थापना करने वाले कानूनों को आम तौर पर एपीएमसी (कृषि उत्पाद विपणन समिति) अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाता है। इन विनियमित मंडियों में, किसानों को अपनी उपज को बाजार मूल्य से कम पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। इन तरीकों ने किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति या वस्तुओं की खातिर एक राष्ट्रीय बाजार के निर्माण में बाधा पैदा की। उदाहरण के लिए, 2010 में बेंगलूर (कुमार2016) में प्याज के औसत थोक मूल्य और औसत खुदरा मूल्य के बीच का अंतर 132% था। फिक्की की एक रिपोर्ट में पाया गया कि आंध्र प्रदेश में फलों और सब्जियों के बाजार में उपभोक्ता से मिलने वाली कीमत का केवल 20% हिस्सा किसान को दिया जाता है। (मुखर्जी2013)

घरेलू बाजार की बाधाओं के अलावा, सरकार ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक रूप से संवेदनशील फसलों (प्याज, आलू, दालें, आदि) की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए निर्यात प्रतिबंध लागू करना और अल्प सूचना पर आयात खोलना जारी रखा है। आर्थिक सर्वेक्षण (2014) में कहा गया:

*आम तौर पर कृषि वस्तुओं के लिए एक तदर्थ व्यापार नीति का पालन किया जाता रहा है, जो अक्सर घरेलू मूल्य की स्थिति के लिए तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में होता है। यह घरेलू और साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार को बड़ी अनिश्चितता में डालता है और व्यवस्था में सबसे नीचे आने वाला किसान इससे बुरी तरह प्रभावित होता है। इससे भारत में अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता होने का विश्वास भी कम होता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादों को लेकर एक स्थिर और दीर्घकालिक व्यापार नीति की ज़रूरत है।*

अंत में, कृषि वायदा बाजार, जिसे सैद्धांतिक रूप से मूल्य आंदोलन पर सूचना के माध्यम के रूप में काम करना चाहिए, वह किसानों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। भारत में कृषि के लिए वायदा बाजार, बाकी कृषि की तरह, नियमन के बोझ से ग्रस्त है। वायदा बाजार से जुड़ा नियामक ढांचा ना केवल बोझिल है, बल्कि अप्रत्याशित भी है, विशेष रूप से उन वस्तुओं के लिए जिन्हें आवश्यक माना जाता है (गुलाटी, चटर्जी और हुसैन 2017)।

### 3. सुधार: कृषि में लाइसेंस-नियंत्रित-सब्सिडी राज का अंत करें

1991 में अर्थव्यवस्था का अविनियमन औद्योगिक क्षेत्र पर केंद्रित था; तब से दशकों बाद भी कृषि नीति कृषि वस्तुओं की खेती, प्रसंस्करण और बिक्री के उदारीकरण से दूर रही है। सूखे या बाढ़, मूल्य वृद्धि या दुर्घटना, कर्ज के बोझ या किसानों की आत्महत्या के बावजूद, कृषि पर सरकारी नियंत्रण कमोबेश अडिग रहा है (मित्रा 2018)। किसान अब भी एक गहन नियंत्रित विनियमन के माहौल में संघर्ष कर रहे हैं और जी रहे हैं। वे उन नियंत्रणों का सामना कर रहे हैं जो अर्थव्यवस्था के किसी अन्य क्षेत्र में अकल्पनीय हैं।

निचले खंड में, हम उन सात क्षेत्रों - भूमि, हाजिर बाजार, वायदा बाजार, मूल्य हस्तक्षेप, इनपुट सब्सिडी, ऋण बाजार और बीजों में प्रौद्योगिकी - पर ध्यान दे रहे हैं जहाँ सरकारी हस्तक्षेप या तो असफल या अनुपस्थित है। प्रत्येक खंड सुधार संबंधी विचारों के बाद आने वाली समस्याओं का एक संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करता है।

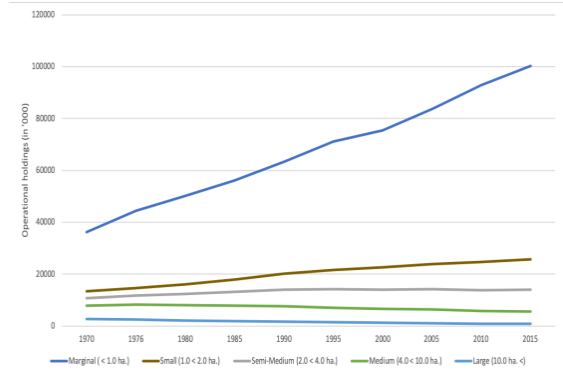
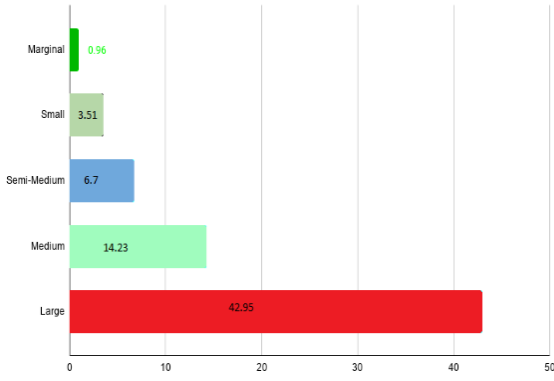
### 1. भूमि स्वामित्व, बिक्री, काशतकारी और इस्तेमाल पर लगी रोक हटाएँ

एक किसान की प्रमुख पूंजी संपत्ति कृषि भूमि है जिसका भारत में काफी विनियमन होता है। राज्य स्तर पर अधिनियमित कानूनों का मेल, भूमि की बिक्री, खरीद, उपयोग और पट्टे को प्रतिबंधित करता है। भारतीय गणतंत्र के गठन के शुरुआती वर्षों में पेश किए गए इन प्रतिबंधों का उद्देश्य: 1) किसानों को विशेष रूप से जमींदारों या जमींदारों द्वारा शोषण से बचाना, और 2) कृषि अर्थव्यवस्था में दक्षता और निवेश में वृद्धि करना था (नीति आयोग 2016, पेज. 4)। हालांकि, इन प्रतिबंधों से वांछित परिणाम नहीं मिले। निम्नलिखित पैराग्राफ में, हम संक्षेप में इन कानूनों और उनके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। यह खंड कृषि भूमि दस्तावेजों के रखरखाव में कमियों पर भी प्रकाश डालता है और बताता है कि यह भूमि बाजार को कैसे प्रभावित करता है।

**किसी व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व वाली भूमि के आकार पर सीमा लगी है।**

1950 और 60 के दशक में, पूरे देश की राज्य सरकारों ने कृषि भूमि के उस आकार को प्रतिबंधित करने वाले कानून पेश किए, जिस पर एक व्यक्ति या एक परिवार का स्वामित्व हो सकता है (पाल 2019)। बोई गई फसल के प्रकार (नकद या भोजन), मिट्टी की उर्वरता (सूखी या गीली) और परिवार के आकार जैसे कारकों के आधार पर राज्यों में सीमा अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में अधिकतम सीमा 10 एकड़ से लेकर 54 एकड़ (आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (कृषि जोत की सीमा) अधिनियम 1973 की धारा पांच उपधारा एक) है। भारत की मरुस्थलीय भूमि के एक महत्वपूर्ण हिस्से वाले राज्य राजस्थान में भूमि जोत के लिए 18 एकड़ की सीमा है जहाँ एक वर्ष में दो फसलें उगायी जा सकती हैं लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्रों में आने वाले जोतों के लिए यह सीमा 175 एकड़ है।

**जोत-आकार पर लगे प्रतिबंधों की वजह से भूमि का विखंडन हुआ है और साथ ही यह किसानों की अपर्याप्त आय का कारण है।**



### क. जोत का औसत आकार

### ख. परिचालन वाले जोत की संख्या

चित्र 6: भारतीय कृषि के लिए लागत और लाभ के संकेतक

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2019ए

भूमि के आकार पर इन सीमाओं की वजह से, भारत में कृषि भूमि काफी खंडित है और छोटी एवं सीमांत जोत का प्रभुत्व है। 2015-16 में, जोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर/2.7 एकड़ था जिसमें 0.18 हेक्टेयर/0.5 एकड़ के साथ केरल तालिका में सबसे नीचे और 5.06 हेक्टेयर/12.5 एकड़ (पत्र सूचना कार्यालय2019) के साथ नागालैंड शीर्ष पर था। इसकी तुलना दक्षिण अमेरिका में 67 हेक्टेयर, यूरोप में 27 हेक्टेयर और उत्तरी अमेरिका में 121 हेक्टेयर के औसत जोत के आकार से करें। इसके अलावा, औसत भूमि जोत का आकार 1970 के दशक से लगातार कम हुआ है। 2015-16 के कृषि सर्वेक्षण में 2010-11 और 2015-16 के बीच 0.07 हेक्टेयर/0.17 एकड़ की गिरावट का पता चला (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2019ए)।

जहाँ एक छोटी जोत अपने आप में उत्पादकता को रोक नहीं सकती है, बाजार नियंत्रणों, अकुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं और खराब अनुसंधान एवं विकास निवेश के साथ आने पर, भूमि के आकार को कृत्रिम रूप से छोटा रखने वाले भूमि सीमा कानूनों का उत्पादकता पर नकारात्मक असर पड़ा है। (घटक और रॉय 2007)। कई शोधकर्ताओं ने कृषि उत्पादकता और किसान आय पर मौजूदा भूमि सीमा कानूनों के नकारात्मक प्रभाव का दस्तावेजीकरण किया है। पाल, सहार और चौधरी (पाल2019) ने पाया कि भूमि के विखंडन से भूमि अधिग्रहण के लेनदेन की लागत बढ़ जाती है और इसकी वजह से पूंजी निवेश और औद्योगिकरण की रफ्तार कम हो जाती। इसके अलावा, काफी छोटी भूमि जोतों से भारत में खेतों के मालिकों के लिए पर्याप्त आय का सृजन नहीं होता (आईडीएफसी फाउंडेशन 2013)।

### भूमि की बिक्री, खरीद, और काशतकारी पर रोक लगे हैं।

भारत में कृषि भूमि की बिक्री पर कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। जहाँ राज्य के कानून विवरण में अलग होते हैं, वे आम तौर पर, कौन जमीन खरीद सकता है (भारतीय निवासी, व्यक्ति या कंपनी, किसान, जनजाति के सदस्य) और हस्तांतरण का स्वीकृत तरीका (उपहार बनाम बिक्री) इनकी सीमा तय करते हैं (हैनस्टेड, नीलसन और ब्राउन 2004)। यहां तक कि कई राज्यों में किसान की परिभाषा प्रतिबंधात्मक है। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश काशतकारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 एक "किसान" को एक ऐसे जमींदार के रूप में परिभाषित करता है जो व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करता है। इन शर्तों के अलावा, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में कृषि भूमि की बिक्री से पहले सरकार की मंजूरी की ज़रूरत के साथ प्रक्रिया से जुड़े प्रतिबंध भी हैं (हसन2016)।

गरीब काशतकारों को भूमि मालिकों द्वारा शोषण से बचाने के इरादे से पेश किए गए कृषि भूमि को पट्टे पर देने संबंधी नियम ज़्यादातर राज्यों में या तो काशतकारी पर प्रतिबंध लगाते हैं या उसे सीमित कर देते हैं। नियमन चार प्रकार का होता है (हैनस्टेड, नीलसन और ब्राउन 2004)। सबसे पहले, कुछ राज्यों में कृषि काशतकारी पर पूर्ण प्रतिबंध है। उदाहरण में केरल और जम्मू और कश्मीर शामिल हैं। दूसरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जो काशतकारी पर प्रतिबंध लगाते हैं लेकिन विधवाओं और नाबालिगों जैसे आबादी के कुछ वर्गों को इस प्रतिबंध से बाहर रखते हैं। एक तीसरी श्रेणी में वे राज्य आते हैं जहाँ काशतकारी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ऐसे कानून हैं जो काशतकारों को मालिक के समान अधिकार देते हैं। पश्चिम बंगाल और गुजरात इस श्रेणी में आते हैं। अंत में, ऐसे राज्य हैं जिन्होंने दोनों तरह के नियमों को अपनाया है: इन नियमों में काशतकारी को सीमित करने वाले नियम और साथ ही पट्टे की उच्चतम सीमा को लागू करके किरायेदारी की प्रकृति को बदलने से जुड़े नियम हैं।

**ये प्रतिबंध कृषि भूमि की कीमत को कम करते हैं, खेती छोड़ने या निवेश हासिल करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं।**

इस तरह की सीमाएं जमींदारों को कई तरह से फंसाती हैं। सबसे पहली, किसानों पर जमीन बेचने की बाध्यता यह मानती है कि सभी भूमि लेनदेन प्रकृति में शोषक हैं और यह जमींदार के खिलाफ जा सकता है; जबकि यह हमेशा सही नहीं होता। दूसरी, भूमि की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध से भूमि की कीमत में कमी आती है; जो भूमि आसानी से नहीं बेची जा सकती, वह अपनी वाजिब कीमत की तुलना में कम कीमत की हो जाती है। तीसरी, यह मालिक को अपनी जमीन से बांध देती है, यहाँ तक कि जो लोग भूमि बेचकर इससे बाहर निकलना चाहते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। इससे किसी के लिए अपनी संपत्ति को बेचना या आय के स्रोतों में विविधता लाना मुश्किल हो जाता है (हैनस्टेड, नीलसन और ब्राउन 2004)। अंत में, कृषि भूमि के लिए काशतकारी के बाजार की अनुपस्थितिकी वजह से काशतकार कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर रहते हैं और यह खेतों में निवेश को सीमित करती है। 2016 में, भारत में केवल 10% कृषि भूमि काशतकारी के अधीन थी (नीति आयोग 2016, परिशिष्ट 10)। इस संबंध में जम्मू कश्मीर 0.15% भूमि पट्टे के तहत सबसे नीचे आता है और आंध्र प्रदेश 30% से अधिक कृषि भूमि पट्टे के साथ शीर्ष पर है। जहाँ 4% किसानों को "मालिक या मालिक जैसे अधिकारों" से लाभ हुआ है, अन्य को या तो भूमि की उपलब्धता के बिना छोड़ दिया गया है या अनौपचारिक रूप से उपलब्धता दी गयी है, इस वजह से शोषण (नीति आयोग 2016) को बढ़ावा मिला है। अविनियमित निजी बाजारों का रुख करने के लिए मजबूर किसान संस्थागत ऋण या राज्य से मदद हासिल करने में विफल रहते हैं (नीति आयोग 2016)।

**इसके अलावा भूमि के इस्तेमाल पर कई रोकटोक हैं।**

ज़्यादातर राज्य कृषि भूमि के इस्तेमाल को कृषि उद्देश्यों तक ही सीमित रखते हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 42 घोषित करती है कि "कृषि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी भूमि का इस्तेमाल किसी भी गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।" अन्य उपयोगों के लिए भूमि को लेकर बदलाव की अनुमति है लेकिन यह एक जटिल व्यवस्था के तहत होगा जिसके लिए कई तरह की मंजूरी लेनी होती है। किसान कोई व्यापार शुरू करने के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल नहीं कर सकते; बेहतर विकल्प उपलब्ध होने पर भी उन्हें खेती ही करनी होगी।

**अंत में, भारत में भूमि बाजार भूमि दस्तावेजों के खराब रखरखाव की समस्या से पीड़ित हैं।**

स्वामित्व स्थापित करने के लिए कई दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। ये दस्तावेज आसानी से उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि रिकॉर्ड डिजिटल नहीं हैं, अधूरे हैं और मैन्युअल रूप से रखे गए हैं। दस्तावेजों को संभालकर रखने की प्रक्रिया में विभिन्न विभाग शामिल होते हैं और अंतर-विभागीय संचार खराब है। जहाँ सरकार ने भूमि दस्तावेजों को अद्यतन (अपडेट) करने के लिए



सर्वेक्षण किए हैं, कोशिशें खत्म नहीं हुई हैं; सटीक और नवीनतम जानकारी के बिना आंशिक डिजीटलीकृत डेटा को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता और वह उद्देश्य पूरा नहीं करता। (मिश्रा और सुहाग 2017)।

भूमि दस्तावेजों की अनुपस्थिति के व्यापक प्रभाव हैं: यह संपत्ति की बिक्री को धीमा कर देता है और फलस्वरूप ढांचागत विकास प्रभावित होता है; सभी लंबित मामलों में से आधे से अधिक भूमि विवादों से जुड़े हैं और उन्होंने न्यायपालिका की उत्पादकता पर असर डाला है; और यह ऋण वृद्धि में बाधा डालता है क्योंकि स्पष्ट स्वामित्व वाली भूमि का मॉर्गेज के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता (मिश्रा और सुहाग 2017)।

**कई प्रतिबंधों को हटाने के लिए सुधार चल रहा है उनकी गति धीमी है।**

चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों को इन प्रतिबंधों में ढील देने या उन्हें हटाने का बीड़ा उठाने की ज़रूरत होगी। 2016 में, नीति आयोग के शोधकर्ताओं ने भूमि पट्टा सुधारों को एक अवयव मानते हुए एक कृषि विपणन और किसान अनुकूल सूचकांक तैयार किया था (चांद और सिंह 2016)। रिपोर्ट के अनुसार, 21 राज्यों ने भूमि पट्टे पर प्रतिबंध लगाया था, और 10 राज्यों ने आंशिक रूप से पट्टे पर देने की अनुमति दी थी।

किसानों के संपत्ति के अधिकार से जुड़े प्रतिबंधों से उबरना मुश्किल है, खासकर इस वजह से क्योंकि इनमें से ज्यादातर प्रतिबंध संविधान की अनुसूची नौ के तहत रखे गए हैं। अनुसूची नौ का निर्माण एक संवैधानिक उपकरण के रूप में किया गया था जिसके साथ विधायिका, न्यायिक समीक्षा के बिना लोगों के एक निश्चित समूह की संपत्ति के अधिकार को छीन सकती थी। न्यायिक समीक्षा के अभाव में, यह बदलाव राज्य विधायिकाओं के माध्यम से आना चाहिए लेकिन राज्य ये सुधार लाने से बचते रहे हैं।

**कुछ राज्यों ने भूमि सीमा कानूनों में ढील देने के लिए सुधार शुरू किए हैं (आउटलुक इंडिया 2011)।**

- उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र काश्तकारी और कृषि भूमि अधिनियम 1948 की धारा 63 और 63-1A में संशोधन किया, जिसने औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भूमि की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंधों में ढील दी (डेव और मोट्टा 2017)। 2019 में, महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोत की सीमा) अधिनियम, 1961 में भी एक संशोधन किया गया था, जिसके साथ 54 एकड़ से अधिक भूमि रखने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए थे (सूर्यवंशी 2019)।
- उदाहरण के लिए, उत्तराखंड के भूमि सीमा अधिनियम, 2003 में भी इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं, जो पहले लोगों को केवल 250 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि खरीदने की अनुमति देते थे। 2011 में पारित एक संशोधन (आउटलुक इंडिया 2011) के माध्यम से सीमा को बढ़ाकर 12.5 एकड़ कर दिया गया था।
- उदाहरण के लिए, कर्नाटक ने कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 की धारा 63 में संशोधन किया और एक व्यक्ति एवं एक परिवार के भूमि स्वामित्व की सीमा को दोगुना कर दिया। राज्य ने गैर-कृषकों को कृषि भूमि की बिक्री की अनुमति देने के लिए धारा 80 में भी संशोधन किया।

इन सुधारों ने किसानों को कैसे प्रभावित किया है, इस पर बहुत कम शोध हुआ है। जैसे-जैसे भूमि की सीमा हटाई जाती है, हाशिये पर रहने वाले किसान भूमिहीन हो सकते हैं और उनके कृषि बाजार से बाहर निकलकर कहीं और रोजगार खोजने की संभावना होती। उस स्थिति में, अन्य क्षेत्रों को अतिरिक्त श्रम शक्ति को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त रूप से उत्साहित होना चाहिए।

केवल किसानों को कृषि भूमि बेचने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया जाना चाहिए और सरकार को संपत्ति के अधिकारों की पहचान और सुरक्षा के लिए दोगुने प्रयास करने चाहिए।

अपनी मुख्य संपत्ति को न बेच पाने से परिवार कम उत्पादकता वाली गतिविधियों में फंसते हैं। 18 राज्यों में 5,000 से अधिक उत्तरदाताओं के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में केवल 5% किसानों ने अपनी जमीन बेची है। 60% से अधिक किसानों ने कहा कि यदि शहर में बेहतर आय के अवसर उपलब्ध होते तो वे खेती का काम नहीं छोड़ते (सीएसडीएस-लोकनीति 2018)। राज्यों को भूमि के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध हटा देने चाहिए। यदि किसान खेती छोड़ना चाहते हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग करना चाहते हैं, शायद छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए, तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

मार्च 2016 में, नीति आयोग ने एक आदर्श भूमि पट्टा अधिनियम (नीति आयोग 2016) प्रस्तावित किया। प्रस्तावित अधिनियम काश्तकारी को कानूनी रूप देने का सुझाव देता है। यह पट्टे की शर्तों को काश्तकारों और जमींदारों द्वारा पारस्परिक रूप से परिभाषित करने की अनुमति देता है। हालांकि, राज्य सरकारों ने इसे लेकर कम रुचि दिखाई है; 2018 तक, तीन राज्यों ने इसमें रुचि दिखाई थी (द हिंदू बिजनेस लाइन 2018)। ऐसा लगता है कि, यह रिपोर्ट लिखे जाने के समय, उत्तराखंड ने एक नीति को अंतिम रूप दे दिया है जिसके तहत किसी भी संस्था, कंपनी, फर्म या स्वयं सहायता समूह को 30 साल के लिए 30 एकड़ कृषि भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति मिले जाएगी (आउटलुक इंडिया 2011)।

इस अधिनियम को लागू करने की जगह एक विकल्प पट्टे पर लगे प्रतिबंध हटाना और कृषि भूमि को नियंत्रित करने के लिए संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 और भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 जैसे कानूनों को अनुमति देना है।

एक सक्रिय भूमि बाजार तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक कि खरीदारों और विक्रेताओं के पास कानूनी प्रणाली द्वारा संरक्षित स्वामित्व के निर्णायक दस्तावेज नहीं हो। राज्य सरकारों को स्वामित्व के हस्तांतरण की जानकारी सहित दस्तावेजों के डिजिटलीकरण को पूरा करने को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दस्तावेज भूमि के स्वामित्व को लेकर सही समय पर और सटीक जानकारी देते हो।

## 2. घरेलू हाजिर वस्तु बाजारों का उदारीकरण करें

अब तक ज़्यादातर राज्यों में किसान केवल सरकार द्वारा संचालित मंडियों में ही उत्पाद बेच सकते थे।

भारत में कृषि वस्तुओं की बिक्री, हाल के समय तक एपीएमसी अधिनियमों के माध्यम से काफी विनियमित थी। 1950 और 60 के दशक में ज़्यादातर राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित, यह अधिनियम कृषि उपज पर एक सरकारी एकाधिकार का निर्माण करता है और मूल्य की तलाश में बाधा पैदा करता है। इस वजह से किसान अकसर कमीशनिंग एजेंटों और व्यापारियों की गुटबाजी और मिलकर किए जाने वाले मूल्य निर्धारण का शिकार बनते हैं। (नाबार्ड 2018)।

बाजार समितियां राजनीतिक शक्ति का स्रोत बन गई हैं और सुधार की किसी भी कोशिश का विरोध करती हैं। इस मुद्दे पर, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण, 2014-15 का यह कहना है:

*ऐसी धारणा है कि बाजार समिति (राज्य स्तर पर) और बाजार समिति का निगरानी करने वाला मार्केट बोर्ड – दोनों में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों का कब्जा है। वे उन लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंटों के साथ गलबहियां करते हैं, जो अधिसूचित क्षेत्र के भीतर एकाधिकार की ताकत का इस्तेमाल करके सत्ता का संचालन करते हैं, कभी-कभी गुटबाजी करके ऐसा करते हैं। माना जाता है कि एपीएमसी में सुधार का यही लोग विरोध कर रहे हैं।*

जहाँ मंडियों में लगाया जाने वाले शुल्क कृषि उपज की बिक्री पर लेन देन की लागत बढ़ा देते हैं, सेवाओं की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती।

समिति का कामकाज विभिन्न हितधारकों पर कई शुल्क और शुल्क लगाता है। खरीदार एक बाजार शुल्क का भुगतान करते हैं और खरीदारों और किसानों के बीच मध्यस्थता करने वाले कमीशन एजेंट लाइसेंस शुल्क का भुगतान करते हैं। वेयरहाउसिंग एजेंटों और लोडिंग एजेंटों सहित सभी सेवा प्रदाता भी शुल्क का भुगतान करते हैं। इनके अलावा, कमीशनिंग एजेंटों द्वारा वसूला जाने वाला कमीशन जैसी अन्य लागतें भी हैं। विशेष रूप से कमीशन शुल्क अधिक है क्योंकि यह शुद्ध आय पर नहीं बल्कि उत्पाद की कुल लागत पर लगाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2015 के अनुमान के अनुसार कुल मिलाकर इन दरों (कर/ब्याज शुल्क/लेवी) से पश्चिम बंगाल में 3% से लेकर आंध्र प्रदेश में 19.5% तक की लागत लगाती है।

संचालन की उच्च लागत के बावजूद, कृषि मंडियों में आधुनिक सुविधाओं का अभाव है और खराब बुनियादी ढांचे के लिए उनकी आलोचना की जाती रही है। उदाहरण के लिए, माप मशीनों से नहीं की जाती है और खाद्य वस्तुओं के भंडारण और प्रशीतित (रेफ्रिजरेट) करने की सुविधाएं सीमित या अनुपस्थित हैं। किसानों को भुगतान प्राप्त करने के लिए लंबी-लंबी कतारों में लगना पड़ता है। नतीजतन, फसल की कटाई के बाद के नुकसान बढ़ रहे हैं; कृषि, बागवानी और पशुधन क्षेत्र में घाटा 2005-06 के 62,875 करोड़ रुपए से 2012-13 में बढ़कर 91,787 करोड़ रुपये हो गया। (नाबार्ड 2018बी)।

लंबे समय से बहुत सारे लोग बाजार घनत्व में सुधार और किसानों को पहुंच देने के लिए एपीएमसी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की दलील देते आ रहे हैं।

साक्ष्य बताते हैं कि अधिक बिक्री चैनलों तक पहुंच से किसानों को लाभ होता है। रिज़र्व बैंक के बुलेटिन ने यह भी अनुमान लगाया कि ज़्यादातर किसानों और व्यापारियों ने एपीएमसी से उत्पादों को गैर-अधिसूचित करने को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा, जिसने किसानों को इन मंडियों के बाहर बेचने की अनुमति दी (भोई और अन्य 2019ए)।

इस बात का डर है कि कृषि उत्पादों की बिक्री से जुड़े प्रतिबंधों को हटाने से कमीशन एजेंटों की मध्यस्थता के अभाव में आपूर्ति और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है, विशेष रूप से अल्पावधि में ऐसा हो सकता है जब नए चैनल विकसित नहीं हुए हों। उदाहरण के लिए, सब्जियों के इन मंडियों से असूचीबद्ध होने के तुरंत बाद मुंबई में कीमतों में गिरावट के कुछ सबूत हैं (झा 2016)। इसके उलट, एक जून से 26 सितंबर 2014 के बीच दिल्ली में सब्जियों की कीमतों के एक अध्ययन से पता चलता है कि सब्जियों को मंडियों से असूचीबद्ध किए जाने पर किसानों को फायदा हुआ, अंतिम कीमत (भट्ट और अन्य 2015) में उनकी हिस्सेदारी बढ़ गयी। हालांकि, कोई निर्णायक साक्ष्य हासिल करने के लिए अध्ययन की अवधि बहुत कम है।

केंद्र सरकार ने सुधार के लिए कुछ कोशिशें की हैं। लेकिन राज्यों की ओर से कार्रवाई सीमित रही है।

एपीएमसी से जुड़ी समस्याओं से वाकिफ केंद्र सरकार ने 2003 में एक मॉडल एपीएमसी अधिनियम और 2007 में एएमपीसी नियमों का प्रस्ताव पेश किया था। केंद्र के एक दशक तक प्रेरित करने के बावजूद, ज़्यादातर राज्य सरकारों ने इन सुधारों को लागू नहीं किया। पेश किए गए सुधार "अपूर्ण, छिटपुट एवं अवास्तविक" (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2017) थे। 2017 में केंद्र सरकार ने एक बार फिर निम्नलिखित विवरणों के साथ मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम (या, एपीएलएम) पेश किया:

1. फलों और सब्जियों का अविनियमन: सरकारी मंडियों में नियमों के कार्यान्वयन को सीमित करना;
2. निजी बाजार/मंडी: निजी बाजार अहातों/थोक बाजार अहातों की स्थापना की मंजूरी देना;
3. एकल व्यापार लाइसेंस: पूरे राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र में एकल लाइसेंस पेश करना;
4. बाजार शुल्क का एक जगह संग्रह: बाजार शुल्क के एकल संग्रह बिंदु की स्थापना और किसी भी रूप में दूसरे शुल्क पर रोक;
5. बाजार के रूप में समझे जाने वाले गोदाम: सरकार को अधिसूचना के ज़रिए गोदाम/साइलो/कोल्ड स्टोरेज या अन्य ऐसी संरचना या बुनियादी ढांचे और सुविधाओं वाली जगह को बाजार के रूप में काम करने के लिए उपयुक्त घोषित करने की मंजूरी देना।
6. प्रत्यक्ष विपणन: प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंस जारी करने की मंजूरी देना, जिससे सरकारी या निजी बाजार अहातों के बाहर संसाधक/निर्यातकों/थोक खरीदारों द्वारा कृषि उपज की सीधी खरीद की अनुमति मिले; और
7. इलेक्ट्रॉनिक व्यापार: व्यापारियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक राष्ट्रीय बाजार में पंजीकरण, नीलामी, बिल, बुक, सौदा करने और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाना।

हमने आदर्श एपीएलएम अधिनियम द्वारा सुझाए गए सुधारों को अपनाने का पता लगाया। जैसा कि तालिका 1 में दिखाया गया है, कुछ खंडित सुधार हुए हैं: कुछ राज्यों ने निजी बाजार अहातों को संचालित करने की अनुमति दी है, कुछ ने विनियमित बाजारों के भीतर सभी व्यापारिक गतिविधियों के लिए एकल लाइसेंस की सुविधा प्रदान की है, और अन्य ने बाजार शुल्क वसूली का एकल-बिंदु स्थापित किया है।

हालांकि कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं:

1. जहाँ मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2017 ने निजी बाजारों की स्थापना की अनुमति दी, इसने लाइसेंस देने की परंपरा को जारी रखा। यदि राज्यों द्वारा इसे अपनाया जाता है, तो निदेशक, धारा 10 के अनुसार, "उचित शर्तों" और शुल्क के अधीन निजी यार्ड के लिए लाइसेंस जारी कर सकता है। ई-व्यापार, डायरेक्ट मार्केटिंग और होलसेल मार्केट के लिए भी लाइसेंस जारी किए जाने हैं।

2. जब इन सुधारों को अपनाया जाता है, तब भी विधायी सुधारों का जमीनी स्तर पर पालन नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, जहाँ उत्तर प्रदेश और गुजरात एकीकृत व्यापार लाइसेंस जारी करने की अनुमति देते हैं, इन राज्यों में 1% से कम लाइसेंस एकीकृत हैं (मिश्रा2019)।

3. कुछ जगहों पर अनुमोदक सुधारों को अतिरिक्त शर्तों के साथ बाधित किया जाता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र राज्य ने निजी बाजारों को कार्य करने की अनुमति दी है, लेकिन यह इन पात्रता शर्तों के अधीन (नगर निगम वाले जिलों में) है: न्यूनतम 10 एकड़ भूमि; लाइसेंस शुल्क 50,000 रुपये; 20 लाख रुपये की बैंक गारंटी और अंत में, कम से कम दो करोड़ रुपये का बुनियादी ढांचा निवेश (नाबार्ड2018)।

**किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 से एक उम्मीद जगती है।**

कोविड -19 के मद्देनजर, सरकार पर कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए शर्तों में ढील देने के लिए जोर डाला गया था। केंद्र सरकार ने पांच जून, 2020 को एक अध्यादेश के माध्यम से, पैन कार्ड वाले व्यक्तियों या सहकारी समितियों को सीधे किसानों से खरीदारी करने की अनुमति दी। यह जटिलता की परतों को महत्वपूर्ण रूप से कम करता है और एक प्राकृतिक बाजार को विकसित करने की अनुमति दे सकता है। जहां अध्यादेश एक स्वागत योग्य कदम है, यह देखा जाना बाकी है कि क्या संसद इसे कानून का रूप देगी। किसानों, व्यापारियों, कमीशन एजेंट - सभी के बीच प्रतिरोध और भय है। निजी व्यापार को मुक्त करने के अलावा, सरकार को हितधारकों के बीच राजनीतिक संबंधों की गहरी जड़ें खोदने के लिए काम करना पड़ सकता है।

सफलता संस्थानों में सुधार करने, एजेंटों को प्रोत्साहन देने और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की राज्यों की क्षमता पर निर्भर करती है। कर्नाटक कृषि सुधार में सबसे आगे रहा है। राज्य पर शोध से पता चलता है कि सफल सुधार के तीन हिस्से हैं (अग्रवाल, जैन और नारायणन 2016): ई-व्यापार को सक्षम और प्रोत्साहित करने के लिए विधायी सुधार, बदलावों के अनुकूल एजेंटों को प्रोत्साहित करना और प्रत्यक्ष एवं वित्तीय भुगतान बुनियादी ढांचे का विकास करना।

Table 1: Status of Deregulation as of May 2020

	Deregulation of Fruits and Vegetables	Private Mandis	Single Trading License	Single Point Levy of Market Fee	Warehouses as Deemed Markets	Direct Marketing	E-Trading
AR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AS	✓	✓	NA	NA	✗	✓	NA
CG	✓	NA	✓	✓	✗	✓	✓
GA	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GJ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HR	✓	✗	✓	✗	✗	NA	✓
HP	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
JH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KA	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
MP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MH	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
ML	✓	✗	NA	NA	✗	NA	NA
MZ	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓
NL	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
OR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA
PB	✓	✓	✓	✓	✗	✓	NA
RJ	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
SK	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓
TN	✗	✗	✓	✓	✗	NA	NA
TS	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TR	✗	✓	NA	NA	✗	✓	NA
UP	✗	✓	✓	✓	✗	NA	✓
UK	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓
WB	✓	✓	✓	✓	✗	NA	✗
CH	✗	✓	NA	✓	✗	NA	NA
DL	✓	✗	✗	✓	✗	NA	NA
J&K	✗	✗	NA	✓	✗	✓	NA
PY	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

### 3. वस्तु वायदा बाजारों को प्रोत्साहन दें

वायदा बाजार कृषि के उदारीकरण के लिए ज़रूरी है। वर्तमान में सरकार उत्पादन, मूल्य निर्धारण, खरीद, विपणन, भंडारण और वितरण सहित आपूर्ति श्रृंखला के हर चरण में हस्तक्षेप करती है। कीमतों को स्थिर करने के लिए बाजार को मैन्युअल तरीके से समायोजित करने के प्रयास सफल नहीं रहे हैं। हाल के एक अध्ययन में, बर्मन और अन्य ने तर्क दिया है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सरकारी हस्तक्षेप से कीमतों में उतार-चढ़ाव आया है - जो मूल्य स्थिरीकरण के इच्छित उद्देश्य के विपरीत है (2018)। इसके बजाए, वायदा बाजार के साथ इच्छित उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है। यह कई काम कर सकता है। उदाहरण के लिए, यह किसानों को बुआई के फैसलों को पिछली कीमतों पर नहीं बल्कि भविष्य की कीमतों पर

आधारित करने में मदद करता है। यह उन्हें अपने उत्पाद के लिए मूल्य लॉक-इन करने की अनुमति देता है और व्यापारियों को आज खरीद एवं कल बिक्री और इसकी उलट व्यवस्था के "इष्टतम" स्टॉक बनाए रखने में सक्षम बनाता है (फाइनेंशियल एक्सप्रेस 1998)।



चित्र 7: थोक मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव

स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2020

**वायदा बाजार खरीदारों और विक्रेताओं की जोखिम से निपटने में मदद करते हैं।**

कृषि क्षेत्र मूल्य अस्थिरता के लिहाज से संवेदनशील है। मांग और आपूर्ति बेलोचदार होती है, यानी मांग या कीमत में गिरावट होने पर भी किसानों को इन बदलावों से तालमेल बिठाने में कम से कम कुछ महीने लग जाते हैं। वायदा बाजार खरीदारों और विक्रेताओं को इन जोखिमों को एक हद तक कम करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, चावल उगाने वाला किसान कई महीने पहले कीमत तय करके खराब मानसून की संभावना को नियंत्रित कर सकता है जो उसकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। कॉफी पेय बनाने वाली कंपनी भी डिलीवरी के महीनों से पहले कॉफी खरीदकर मूल्य वृद्धि के जोखिम से बच सकती है।

वर्तमान में, भारत में कुल कृषि-वायदा व्यापार में किसानों की हिस्सेदारी ना के बराबर है (चटर्जी, गुलाटी और हुसैन 2018)। देश के सबसे बड़े कृषि-वस्तु विनिमय बाजार (एक्सचेंज), नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) कई कारणों से किसानों को वायदा बाजारों में व्यापार करने के अपने मंच पर लाने में संघर्ष करता रहा है। छोटे जोत और ऐसे बाजारों में विश्वास और प्रशिक्षण की कमी किसानों की ओर से भागीदारी में बाधा डालती है।

**कई लोग वायदा बाजार पर अविश्वास करते हैं और मूल्य खोज में इसकी भूमिका को कम आंकते हैं।**

कुछ लोगों को यह चिंता होता है कि वायदा बाजार में भागीदारी से गैर-पारदर्शी मूल्य निर्धारण, हाजिर बाजार में अस्थिरता एवं हाजिर कीमतों में वृद्धि (परिणामस्वरूप, मुद्रास्फीति) होती है। इन चुनौतियों के बावजूद, वेलमुरुगन और इरशाद वीके ने पाया कि वायदा बाजार सूचना के प्रसार, मूल्य की खोज और जोखिम प्रबंधन को सक्षम करने के लिए फायदेमंद हैं; यह अंतर्निहित वस्तु बाजार के विकास में योगदान देता है (पलानीअप्पन, शनमुगम और इरशाद वीके 2017)

अलग से, अग्रवाल और थॉमस (2014) के एक अध्ययन में पाया गया है कि इन बाजारों का मूल्य खोज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी वायदा कीमतों का हाजिर बाजार की कीमतों के साथ एक सकारात्मक संबंध है। हालांकि, इन बाजारों से कीमतों में उतार-चढ़ाव के खिलाफ कोई राहत नहीं मिली। वायदा बाजार ऐसा प्रभावी ढंग से करें इसके लिए, एक ऐसा नियामक वातावरण होना चाहिए जो मध्यस्थता को प्रोत्साहन और सहयोग देता हो (अग्रवाल, जैन और थॉमस 2014)।

**बाजार में मनमाने हस्तक्षेप से इन बाजारों की क्षमता पर असर पड़ा है।**

इंडियन काउंसिल फोर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर) ने 2017 में एक रिपोर्ट में तर्क दिया था कि कृषि वायदा बाजार के खराब प्रदर्शन का एक कारण स्थिर नीतिगत वातावरण की कमी है। भंडारण नियमों में बार-बार और अप्रत्याशित बदलाव, बाजार से माल के अचानक निलंबन और "संवेदनशील" वस्तुओं के व्यापार के लिए उच्च मार्जिन ने सट्टेबाजों को भाग लेने से रोक दिया है। आलू जैसे उत्पादों के लिए, मार्जिन अगस्त 2014 में 100% जितना अधिक था (गुलाटी, चटर्जी और हुसैन 2017)। ऐसा प्रतीत होता है कि नीति निर्माता इन संवेदनशील वस्तुओं पर नियंत्रण छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप वायदा बाजार से मूल्य संबंधी जानकारी काफी भ्रमक है। गुलाटी और अन्य ने पाया कि, 2013 के बाद से, व्यापार कम से कम 15 बार निलंबित किया गया।

अग्रवाल और थॉमस (2014) केंद्र सरकार (ईसीए और एमएसपी), राज्य सरकारों और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के हस्तक्षेप से पैदा होने वाले विभिन्न नियामक बाधाओं को भी उजागर करते हैं। साथ में वे बाजार में संगठनों के विश्वास को कम करने वाले बाजार का "सूक्ष्म प्रबंधन" करते हैं। इसके अलावा, निपटान से संबंधित समस्याएं भी हैं। "विनिमय-पंजीकृत गोदामों में वितरित वस्तुओं की मात्रा और गुणवत्ता के रूप में निपटान की अनिश्चितता या जारी किए गए गोदाम रसीदों के संबंध में अनिश्चितता वायदा और हाजिर मूल्य के बीच की कड़ी में अनिश्चितता पैदा करते हैं।"

**किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है।**

जहाँ किसान खुद को सीधे वायदा बाजार में भाग लेने में असमर्थ पाते हैं, किसान-उत्पादक संगठन (एफपीओ) या ऐसा कोई एग्रीगेटर, यहाँ एक भूमिका निभा सकता है। जहाँ उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास हुए हैं, वहीं अब तक उनकी भागीदारी कम ही रही है। अप्रैल 2016 और मई 2018 के बीच, एनसीडीईएक्स पर सभी वायदा लेनदेन का केवल 0.004% एफपीओ के माध्यम से किया गया था। बाजार में कारोबार करने वाले 80 एफपीओ में से 80% ने केवल एक बार कारोबार किया (चटर्जी, रघुनाथन और गुलाटी 2019)। किसानों और बिचौलियों के बीच मजबूत संबंधों, एफपीओ क्षमता की कमी और बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति कम भागीदारी की वजहें हैं। इनके अलावा, केवाईसी मानदंड, उच्च सदस्यता शुल्क और मार्जिन शुल्क हैं जो प्रवेश के लिए बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं (डे, गांधी और देबनाथ 2019)।

**भारत सरकार को कल्याणकारी राज्य के दृष्टिकोण को पीछे छोड़ने और एक मजबूत नियामक ढांचा विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।**

एक विश्वसनीय वायदा बाजार किसानों को राज्य द्वारा निर्धारित एमएसपी के बजाय मूल्य की खोज के लिए वायदा बाजार पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जैसा कि अग्रवाल और थॉमस बताते हैं, सरकार को केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों पर रोक लगा देनी चाहिए, एक नियामक ढांचा तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए जो उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देता हो और दुरुपयोग की संभावना को कम करता हो (अग्रवाल, जैन और थॉमस 2014)। राज्य की खरीद, निजी भंडारण पर प्रतिबंध और आयात-निर्यात नियंत्रणों के इस्तेमाल जैसी बाजार का प्रभावित करने वाली गतिविधियों को खत्म करना भी महत्वपूर्ण है। अगर जरूरी हो, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार का इस्तेमाल अपर्याप्त वस्तुओं की खरीद या अधिकता की स्थिति में वितरण के लिए किया जा सकता है।



## हमें चीन से कुछ सीख लेनी चाहिए।

भारत और चीन छोटे और सीमांत किसानों के प्रभुत्व के मामले में समान हैं, जो हमें उनके दृष्टिकोण का विश्लेषण और तुलना करने की अनुमति देता है। 2016 में वायदा बाजार ने दुनिया भर में 1.6 अरब से अधिक अनुबंधों पर कारोबार किया। इनमें चीन ही हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा 69% थी, दूसरी तरफ भारत की हिस्सेदारी महज 2% थी।

चीन को भारत के वायदा बाजार से अलग करने वाले पहलुओं में से एक यह है कि चीन के चाइना नेशनल सीरियल्स, ऑयल्स एंड फूडस्टफ्स कॉरपोरेशन (सीओएफसीओ) जैसे सरकारी व्यापारिक उद्यम भी वायदा बाजार का हिस्सा हैं। साथ ही, चीन में सभी कृषि अनुबंध डिलीवरी आधारित हैं, जो अस्थिरता को कम करता है। ये नीतियां नियमों में मनमाने ढंग से बदलाव करने के लिए नियामक प्रोत्साहन को कम करने और विश्वास का सृजन करने में भूमिका निभाती हैं (गुलाटी, चटर्जी और हुसैन 2017)।

साथ ही, 2005 से, चीन ने किसानों को वायदा बाजार (द हिंदू बिजनेस लाइन 2019) में शामिल होने की खातिर प्रोत्साहित करने के लिए 'हजारों गाँवों और हजारों किसानों' जैसी योजनाएं और अभियान शुरू किए हैं। चीन के अनुभव से आकर्षित होकर, आईसीआरआईआईआर इस बात पर प्रकाश डालता है कि सरकार किसान प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से किसानों की भागीदारी का समर्थन करने में एक आवश्यक भूमिका निभा सकती है (गुलाटी, चटर्जी और हुसैन 2018)। वस्तु बाजार में अधिक भागीदारी से एमएसपी योजना के तहत आने वाली वस्तुओं की संख्या में कमी आने की संभावना है। भारत में, किसानों को वायदा बाजार की बुनियादी चीजों के संबंध में प्रशिक्षण उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाने के लिए जरूरी है। साथ ही खास तौर पर उन सांस्कृतिक धारणाओं में बदलाव करने के लिए जागरूकता का निर्माण करना जरूरी है, जो वायदा बाजार में व्यापार को जुए के समान बताती हैं।

## 4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगी रोक हटाएँ

1950 के दशक में, भारत खाद्य वस्तुओं की कमी का सामना कर रहा था और आयात पर निवेश करने के लिए हमारे पास सीमित विदेशी मुद्रा पूंजी थी। इसलिए खाद्य सुरक्षा एक प्राथमिकता बन गई। 1960 के दशक के मध्य में अमेरिका ने भारत पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में खाद्य सहायता का इस्तेमाल किया, तो इससे अपनी खाद्य खपत की जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने का भारत का संकल्प मजबूत हुआ। इन चिंताओं पर ध्यान देते हुए भारत ने बाद के दशकों में एपीएमसी अधिनियम सहित कई प्रतिबंध लगाए, और उत्पादकों को एमएसपी की पेशकश की। इसके अलावा, भुगतान खाते के सकारात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए, विदेशी मुद्रा का उपयोग कृषि आदानों के आयात तक सीमित कर दिया गया। यहाँ तक कि खाद्य तेल जैसी उच्च-मांग वाली वस्तुओं का भी आयात नहीं किया जा रहा था।

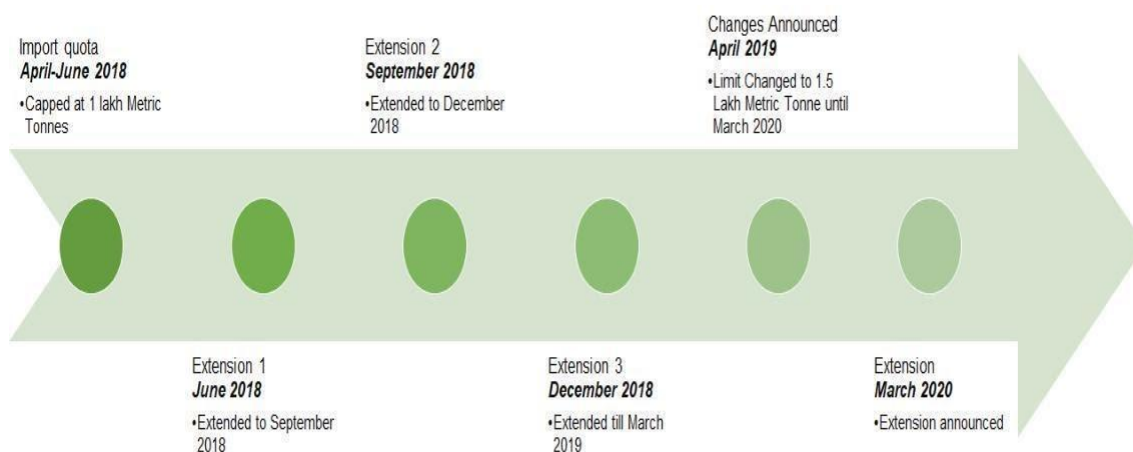
आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 (सुब्रमण्यम 2020) मुक्त व्यापार के लिए सरकारों के व्यापारिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है, यानी, व्यापार घाटे और आत्मनिर्भरता को लेकर अहम चिंताओं को दर्शाता है। इस तरह का दृष्टिकोण बुनियादी व्यापार सिद्धांत के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है जहां व्यापार घाटे पर जोर नहीं दिया जाता है बल्कि मुक्त व्यापार से पैदा होने वाले संसाधनों के कुशल आवंटन से होने वाले लाभों पर जोर दिया जाता है। निर्यात और आयात नियंत्रणों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बार-बार हस्तक्षेप और मुक्त व्यापार पर घरेलू उपभोग की जरूरतों को तरजीह देने से स्थिर व्यापार संबंधों के विकास में बाधा पैदा होती है।

2019 ट्रेड बैरियर इंडेक्स कुल 86 देशों को उनके व्यापार बाधाओं के इस्तेमाल के आधार पर रैंक करता है। शुल्क प्रतिबंधों का इस्तेमाल करने के खराब रिकॉर्ड के साथ, भारत सूचकांक में सबसे नीचे है। जहां 86 देशों में शुल्कों के लिए औसत स्कोर 5.17 (1.83 के मानक विचलन के साथ), गैर-शुल्क माप 1.87, सेवा प्रतिबंध 4.38, और सुविधा 4.57 है, भारत का स्कोर क्रमशः 6.01, 8.11, 3.61, 7.17, और 5.16 है। रिपोर्ट में भारत को 'व्यापार उदारवाद के सबसे बुरे उल्लंघनकर्ता' (2019) के रूप में टैग किया गया है। अमेरिका के कृषि विभाग का कहना है कि **कई बुनियादी खाद्य वस्तुओं के लिए आत्मनिर्भरता की तलाश में, भारत की व्यापार नीति ने निर्यात नियंत्रणों और जरूरत से ज़्यादा प्रतिबंध लगाने वाली आयात व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है... ऐसी संरक्षणवादी नीतियां भारत के प्रति व्यक्ति कृषि आयात को कम कर देती हैं।**

**आयात नियंत्रणों का खुलकर इस्तेमाल और आयात नीतियों में बार-बार बदलाव।**

कृषि उत्पादों पर भारत की शुल्क दरें, 100-300 प्रतिशत के बीच, दुनिया में सबसे अधिक हैं। यह 113.5 प्रतिशत की औसत विश्व व्यापार संगठन-बाध्य दर और 32.8 प्रतिशत की औसत लागू दरों के साथ है। बाध्य और लागू दरों के बीच बड़े अंतर का इस्तेमाल करते हुए, सरकार घरेलू उत्पादकों को सहारा देने के लिए आयात शुल्क की संरचना में लगातार बदलाव करती है।

उदाहरण के लिए, 2017 में भारत ने काबुली चने पर आयात शुल्क शून्य प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत, मटर पर 50 प्रतिशत, बड़े काबुली चने पर 40 प्रतिशत और दालों पर 30 प्रतिशत कर दिया। इसके अलावा, 2018 के बजट में, केंद्र सरकार ने फलों के रस (30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत), और खाद्य वनस्पति तेलों (20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत) सहित 52 अलग-अलग सामानों पर शुल्क बढ़ा दिया (यूएसआईटीए 2020)।



चित्र 8: पीले चने के लिए आयात का कोटा

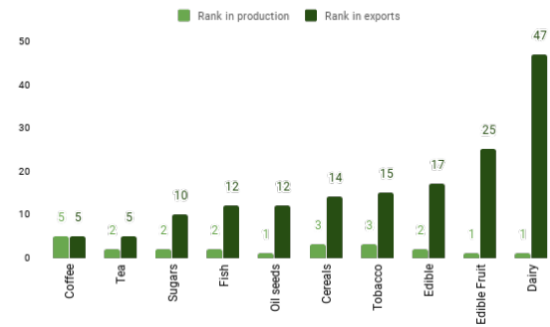
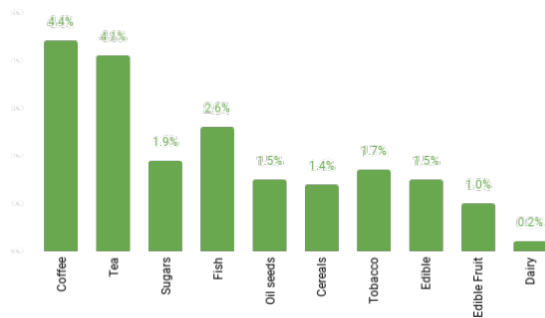
स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

**उच्च उत्पादन के बावजूद, भारत का वैश्विक कृषि व्यापार में योगदान कम है।**

भले ही भारत कई कृषि वस्तुओं के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, हमारा कृषि निर्यात वैश्विक कृषि व्यापार का केवल 2% है। भारत के लगभग सभी कृषि निर्यात कम मूल्य वर्धित सामान हैं। ज़्यादातर निर्यात कच्ची और अर्ध-प्रसंस्कृत वस्तुएं के हैं।

मूल्य के लिहाज से भारत की निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का केवल 15% हिस्सा मूल्यवर्धित या उच्च मूल्य वाली वस्तुएं हैं (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 2019)।

इसके कई कारण हैं: बड़ी घरेलू खपत, निर्यात करने वाले देशों की जरूरतों से मेल नहीं खाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और एक अस्थिर व्यापार नीति। छोटी जोत और फसल के बाद के बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति किसानों को वैश्विक स्वच्छता और पादप (पौधों की) स्वच्छता मानकों को पूरा करने से रोकती है।



क. विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा

ख. उत्पादन और

निर्यात में भारत का रैंक

चित्र 9: भारत की निर्यात स्थिति

स्रोत: दलवाई 2017

**तदर्थ और संरक्षणवादी नीति वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को कम करती है।**

भारत की संरक्षणवादी व्यापार नीतियां और निर्यात की प्रकृति अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कम योगदान के प्रमुख कारण हैं। भारत ने अक्सर और मनमाने ढंग से कोटा, शुल्क, प्रतिबंध और न्यूनतम निर्यात मूल्य के माध्यम से निर्यात को प्रतिबंधित करने के विभिन्न तरीकों का सहारा लिया है।

जून 2017 तक, कई उत्पादों का निर्यात प्रतिबंधित रहा। इसमें मटर, दाल, मूंग, उड़द, सेम, अरहर, और वनस्पति तेल जैसे सोयाबीन, मूंगफली, पाम, सूरजमुखी का तेल आदि शामिल हैं। तालिका 2 2004-05 से 2013-14 के बीच निर्यात प्रतिबंधों के रुझानों पर प्रकाश डालती है। लेखकों ने पाया कि अध्ययन की गयीं 15 वस्तुएं 17% समय गैर-व्यापारिक क्षेत्र में थीं (X द्वारा इंगित)।

भारत की निर्यात नीति पर उपभोक्ता के गहरे पूर्वाग्रह और खाद्य वस्तुओं की कमी की आशंका का प्रभाव पड़ता है। इसकी आलोचना करते हुए, नवीनतम कृषि निर्यात नीति इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे सरकार "मुद्रास्फीति पर काबू पाने के अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में व्यापार नीति" का इस्तेमाल करती है। नीति यह भी नोट करती है कि कैसे इस तरह की प्रथाओं को निरंतर मैन्युअल समायोजन की आवश्यकता होती है और बाजार में तनाव और अनिश्चितता पैदा होती है।

**नई कृषि निर्यात नीति में एक स्थिर व्यापार व्यवस्था की परिकल्पना की गई है।**

ऐसे संकेत हैं कि कम से कम निर्यात का माहौल बदल रहा है। 2018 में, सरकार ने 2022 तक कृषि निर्यात के मूल्य को दोगुना कर 60 अरब अमरीकी डालर (4.3 लाख करोड़) करने और फिर 100 अरब अमरीकी डालर करने की उम्मीद के साथ कृषि निर्यात नीति को अपनाया। इस बात का संज्ञान करते हुए कि यह क्षेत्र लंबे समय से एक "स्पष्ट और पूर्वानुमेय निर्यात नीति" की मांग करता रहा है, संशोधित नीति, एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच के बाद अस्थायी नियामक बदलावों और कार्रवाई को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नीति का लक्ष्य तीन चीजें करना है: बंदरगाहों एवं महत्वपूर्ण सड़क और रेल बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्यात की सहायता के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना; निर्यात के लिए विभिन्न बाधाओं की पहचान करने के लिए राज्य के विभागों को अधिकार देना; और एपीएमसी अधिनियम में सुधार करना।

**हालांकि, प्राथमिक कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।**

हालांकि नीति, प्रसंस्कृत और जैविक उत्पादों को निर्यात प्रतिबंधों के दायरे से हटाती है, फिर भी यह कई वस्तुओं, विशेष रूप से "प्राथमिक कृषि उत्पादों" के लिए ऐसा नहीं करती। भारत की तीन सबसे बड़ी निर्यात वस्तुएं - चावल, समुद्री उत्पाद और मांस हैं। अकेले इन तीन श्रेणियों की भारतीय निर्यात में आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी है।

Table 2: Trade status of select commodities, 2004-05 to 2013-14

	Cotton	Sugar-refined	Buffalo meat	SMP	Onion	Banana	Alphonso	Potato	Wheat	Rice	Maize	Gram	Soy-bean	GN	R&M
2004-05	✓	M	✓	✓	✓	✓	M	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
2005-06	✓	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
2006-07	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
2007-08	✓	M	✓	✓	✓	✓	M	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2008-09	✗	M	✓	✗	✓	✓	M	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
2009-10	✓	M	✓	M	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	M	✓	✓
2010-11	✓	✗	✓	M	✓	✓	M	✓	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2011-12	✓	✓	✓	M	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
2012-13	✓	M	✓	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
2013-14	✓	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	M	✓	✓

✓ = exportable ✗ = non-tradable M = import-competing (price of imported goods is lower than domestic price)

GN = Groundnut, R&M = Rapeseed and Mustard seed, and SMP = Skimmed Milk Powder.

Source: Saini and Kozicka 2014

## 5. सरकारी खरीद की कीमत तय करना बंद करें और उसे तर्कसंगत बनाएँ

कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण से जुड़ी भारत सरकार की नीति के दो विपरीत उद्देश्य हैं: मुद्रास्फीति से बचाव करते हुए उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। इसे प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्न खरीदती है, आबादी के कमजोर वर्गों को खाद्यान्न वितरित करती है और एक बफर बनाए रखती है।

एफसीआई की स्थापना 1965 में खाद्यान्नों की कमी के समय में बैक-अप प्रदान करने के लिए की गई थी। हालांकि, यह अब भारत में खाद्य आपूर्ति का सबसे बड़ा खरीदार और जमाखोर बन गया है। अनिवार्य रूप से, यह एक उदाहरण है कि सरकार के

कानून और कार्य समय के साथ नहीं बदलने पर कैसे एक "आपदा-उन्मुख नीति" एक "समान विकास प्रदान करने के साधन" में बदल गई। (सैनी और कोज़िका 2014)।

### सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद करती है।

1965 में स्थापित कृषि लागत और मूल्य आयोग, 23 फसलों की कीमतों पर सलाह देता है, जिसमें सात प्रकार के अनाज, पांच दलहन, सात तिलहन और चार वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। आयोग मांग और आपूर्ति, उत्पादन लागत, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य प्रवृत्तियों, अंतर-फसल मूल्य समता और उपभोक्ताओं पर प्रभाव के विश्लेषण के माध्यम से एक मूल्य तय करता है। इसके लिए आयोग किसानों की बात को समझने के लिए राज्य के दौरों के अलावा राज्य सरकारों और कुछ राष्ट्रीय संगठनों से बातचीत करता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) समर्थन मूल्य पर अंतिम फैसला लेती है। आयोग के विचारार्थ विषय व्यापक हैं। इनमें "उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने और उत्पादन के तरीके विकसित करने के लिए उत्पादक को प्रोत्साहन प्रदान करने की ज़रूरत" से लेकर "भूमि, पानी और अन्य उत्पादन संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग" तक अलग-अलग उद्देश्य शामिल हैं।

एफसीआई एमएसपी पर फसलों की खरीद के लिए जिम्मेदार है। यह प्रणाली सभी राज्यों में एक समान नहीं है; यह पूर्वी क्षेत्रों में कम सक्रिय है। खरीदे गए सामानों में भी भिन्नता है - सरकार केवल गेहूँ, चावल और कपास जैसी वस्तुओं के लिए अंतिम सहारे वाले खरीदार के रूप में काम करती है (ओईसीडी 2018)।

### न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारी खरीद के आधार पर उत्पादन को कम करके बाजार को विकृत करता है न कि बाजार की मांग के आधार पर।

स्वतंत्रता के बाद के युग में शुरू की गई मूल्य निर्धारण प्रणाली, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य आपूर्ति की कमी से निपटने के लिए बनाए गए एक बड़े पैकेज का एक हिस्सा है (चंद 2019)। हालांकि, अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है और यह कई आर्थिक अक्षमताओं में योगदान दे रहा है।

सबसे पहले, यह कृत्रिम रूप से आपूर्ति को बदल देता है। सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे खरीद के तरीकों ने किसानों के साथ फसलों की बुआई के तरीकों को प्रभावित किया है। किसान मांग और आपूर्ति के आधार पर नहीं बल्कि राज्य की खरीद को ध्यान में रखते हुए फसलों की बुआई करते हैं। चावल और गेहूँ जैसे अनाज के लिए, भारत सरकार बाजार अधिशेष का 40-50% खरीदती है, जिससे वह इन अनाजों की सबसे बड़ा खरीदार बन जाती है। पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में प्राप्त बाजार अधिशेष का अनुपात 80-90% तक चला जाता है। इससे चावल, गेहूँ और गन्ने की अत्यधिक बुआई हुई है और किसान दलहन और मोटे अनाज की बुआई से दूर हो गए हैं। सरकार के व्यवहार ने निजी बिक्री को बाहर करते हुए एकाधिकार पैदा कर दिया है।



चित्र 10: चावल और गेहूँ के बफर नियम बनाम वास्तविक भंडार, 10 लाख टन में, 2001-19

दूसरा, यह मूल्य विकृतियों की ओर जाता है। एमएसपी ने न्यूनतम मूल्य के रूप में काम नहीं किया है, बल्कि यह किसानों को मिलने वाला अधिकतम मूल्य बन गया है।

अंत में, एफसीआई की खरीद लागत किसानों को भुगतान की गई कीमत का 25-30% तक बढ़ जाती है, इससे खरीद और वितरण की प्रणाली महंगी होती है। इसी तरह, वितरण लागत किसानों को मिलने वाली कीमतों के 20-25% के बीच है (चंद2019)। उदाहरण के लिए, 2015-16 में, एफसीआई ने 1,467 रुपये के एमएसपी की पेशकश करने के लिए 730 रुपये प्रति क्विंटल का भारी खर्च किया।

सरकार अनाज की एक बड़ी जमाखोर है। भंडार लगातार आधिकारिक मानदंडों को पार करते रहे हैं। इन प्रवृत्तियों ने भारत में खाद्य बाजार का राष्ट्रीयकरण करते हुए निजी निवेश को हाशिए पर डाल दिया है और बाजार पर व्यापक असर डाला है (सैनी201 और कोजिका4)। लगातार बने हुए ऊंचे बफर स्टॉक ने राजकोषीय घाटे में योगदान दिया है। एक जून 2020 को, एफसीआई ने 9.7 करोड़ मीट्रिक टन का अनाज भंडार जमा किया था। इसमें से कम से कम पांच करोड़ मीट्रिक टन "अतिरिक्त भंडार" है। इससे 1,00,000 करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं और राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिल सकती है (गुलाटी 2020)। अशोक गुलाटी लिखते हैं कि इन अतिरिक्त भंडार को मौजूदा बाजार दरों पर बेचने से "इसकी पूरी आर्थिक लागत की वसूली नहीं होगी, क्योंकि वे मौजूदा बाजार कीमतों की तुलना में बहुत अधिक हैं," हालांकि, इन भंडारों को बनाए रखने का मतलब है कि एफसीआई को "हर साल करीब 8,000-10,000 करोड़ रुपए का गैरजरूरी ब्याज शुल्क" देना पड़ेगा (गुलाटी 2020)।

**उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण अक्षम और अप्रभावी है।**

उचित मूल्य की दुकान प्रणाली का संचालन कई अक्षमताओं से भरा हुआ है। गरीबों के उच्चतम अनुपात वाले राज्यों में, रिसाव अधिक है, और खपत की जरूरतें मुख्य रूप से खुले बाजार के माध्यम से पूरी की जाती हैं। सैनी और कोजिका ने बताया कि "गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के 30 प्रतिशत से अधिक हिस्से वाले राज्यों में, कुल खपत का 20 प्रतिशत से कम पीडीएस (जन वितरण प्रणाली) के माध्यम से पूरा किया गया था (सैनी और कोजिका 2014, पेज. 32)।"

**आवश्यक वस्तु अधिनियम ने गोदामों में निजी निवेश को रोक दिया है।**

आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) 1955 सरकार को तेल, दाल और अनाज जैसे खाद्य पदार्थों सहित चुनिंदा वस्तुओं के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। अधिनियम राज्य को जमाखोरी और अधिसूचित वस्तुओं की कीमत पर ऊपरी सीमा लगाने का अधिकार देता है (भयानी और झा 2014)। जहाँ इसके अधीन वस्तुओं की संख्या में काफी कमी आई है, सरकार के पास अधिनियम के तहत किसी भी उत्पाद को आवश्यक होने पर अधिसूचित करने का अधिकार है (एफएओ2005)। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार "ईसीए के तहत वस्तुओं पर लगातार और अप्रत्याशित रूप से भंडारण की सीमा लागू करने से न तो कीमतें कम होती हैं और न ही कीमतों में उतार-चढ़ाव कम होता है। हालांकि, इस तरह के हस्तक्षेप से किराए की मांग और उत्पीड़न के अवसर मिलते हैं। उदाहरण के लिए, 2006 की तीसरी तिमाही में दाल पर भंडारण की सीमा लागू करना, 2009 की पहली तिमाही में चीनी और सितंबर 2019 में प्याज पर भंडारण की सीमा लागू करने से कीमतों पर दबाव कम करने के उद्देश्य के उलट थोक और खुदरा कीमतों को आसान बनाने के बजाय उनकी अस्थिरता तेज हो

गयी। भंडारण सीमा को लागू करने से जुड़ी इस तरह की व्यापक शक्तियों का अक्सर मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जाता है और ये निजी भागीदारों को भंडारण और गोदाम में निवेश करने से रोकती हैं।

नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) सहित कई संगठनों ने कृषि वस्तुओं को अधिनियम के दायरे से हटाने का सुझाव दिया है (शर्मा2017)। अविनियमन निजी निवेश को बढ़ावा देगा, बाजार दक्षता में वृद्धि करेगा और फसल के बाद के नुकसान को कम करेगा (एफएओ2005)।

**यदि समर्थन आवश्यक समझा जाता है, तो सरकार को कम विकृत उपाय अपनाना चाहिए।**

किसान पर किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि वे एमएसपी पर खरीद को लाभकारी मानते हैं और चाहते हैं कि समर्थन जारी रखा जाए (भोई और अन्य 2019)। यदि किसान समर्थन आवश्यक समझा जाता है तो किसानों को राहत ऐसी होनी चाहिए कि इससे फसल बुआई के तरीके प्रभावित न हो। उदाहरण के लिए, 2017 में नीति आयोग द्वारा जारी तीन वर्षीय कार्य योजना में चुनिंदा फसलों के लिए खरीद को सीमित करने का प्रस्ताव रखा गया था। बाकी के लिए, किसान "कीमत की कमी वाले भुगतान" के अनुसार हैं। इस प्रणाली के तहत, किसानों की प्रतिपूर्ति, एमएसपी और सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाने वाले बाजार मूल्य के बीच के अंतर का अनुपात है (2017)।

**चीन से सीख - "न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद कार्यक्रम" से "उत्पादक मुआवजा प्रणाली" तक।**

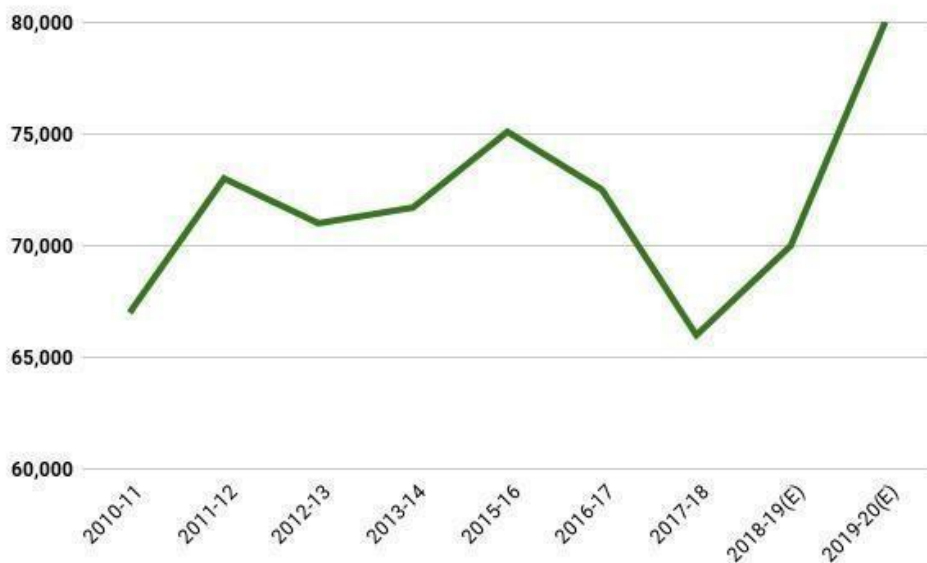
पिछले दशक में, ऊँची अंतरराष्ट्रीय कीमतों के समय, चीन ने चावल, गेहूँ, मक्का और सोयाबीन जैसी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए "न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद कार्यक्रम" शुरू किया। हालांकि, समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण चीन के इतिहास में पहली बार अंतरराष्ट्रीय दरों की तुलना में घरेलू कीमतों में बदलाव आया है। घरेलू रूप से उत्पादित अनाज (विशेष रूप से मक्के) की कीमत आयातित अनाज से अधिक थी। उच्च समर्थन मूल्यों से उत्साहित, किसानों ने सरकार को मकई की बिक्री में वृद्धि की क्योंकि यह अधिक लाभदायक हो गया था। नतीजतन, सरकार के मकई का भंडार 2007 में चार मीट्रिक टन से बढ़कर 2016 में 200 मीट्रिक टन हो गया, जिससे सरकार के लिए खरीद जारी रखना असंभव हो गया। 2016 में, राज्य ने प्रत्यक्ष भुगतान की नीति यानी "उत्पादक मुआवजा प्रणाली" अपनायी। एक वर्ष के भीतर, विकृतियों को उलट दिया गया: घरेलू कीमतें आयात कीमतों से कम हो गईं; आयात गिर गया और मक्के का स्थानीय उत्पादन कम हो गया। भारत की स्थिति को देखते हुए, एफसीआई का भंडार लगातार मानदंडों से ज़्यादा होने के साथ, ऐसी ही एक नीति अपनाने से बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। (स्रोत: चंद2018)

## 6. निवेश सस्मिडी से प्रत्यक्ष हस्तांतरण की ओर बढ़ें

भारत सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के इनपुट-उर्वरक, बिजली, और पानी, बीज एवं बैंक ऋण पर सस्मिडी देती है। सरकार की कार्रवाई राजनीतिक हितों सहित कई कारकों से प्रेरित होती है। लिखित रूप में, हालांकि, दो परस्पर विरोधी उद्देश्य व्याप्त हैं: किसानों का समर्थन करना लेकिन साथ ही उपभोग के लिए सस्ती खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना।

**उर्वरक, बिजली और पानी सस्मिडी वाले प्रमुख इनपुट हैं।**





चित्र 11: उर्वरकों पर केंद्र सरकार की सब्सिडी (करोड़ रुपए में)

स्रोत: गुलाटी और बनर्जी 2015 तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 2020

सरकार, यूरिया निर्माताओं को सब्सिडी के माध्यम से, किसानों को कम लागत पर उर्वरक उपलब्ध कराती है। दूसरी ओर, उत्पादन लागत से कम राशि पर किसानों को सीधे बिजली की आपूर्ति की जाती है। बिजली की तरह ही पानी भी रियायती दाम पर उपलब्ध कराया जाता है। जहाँ किसान भूजल पर काफी ज़्यादा निर्भर हैं, सरकार सतही जल उपलब्ध कराने के लिए नहरों और बांधों जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है। इन तीनों के अलावा, सरकार बीज, कीटनाशक, डीजल और सिंचाई मशीनरी पर भी रियायत देती है।

**इनपुट के सब्सिडीकरण ने बजट का खर्च काफी बढ़ाया है।**

ऋण सहित इनपुट पर सब्सिडी देने से जुड़े भारत के खर्च के नवीनतम अनुमान बताते हैं कि खर्च 235.5 अरब रुपये तक पहुंच गया। हाल के वर्षों में वृद्धि के साथ उर्वरक सब्सिडी इस व्यय का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है (रामस्वामी 2019)। बिजली की हिस्सेदारी 38% से अधिक है। भारत के वित्त आयोग की गणना से पता चलता है कि ये सब्सिडी किसानों की आय का 20% है।

2007 में, कृषि उत्पादन के अनुपात के रूप में सब्सिडी पर भारत का खर्च 9.6% था। यह ब्राजील, रूस और चीन (ग्रॉसमैन और कार्लसन 2011) की तुलना में अधिक था। 1995 की शुरुआत में भारतीय कृषि में इनपुट सब्सिडी के अर्थव्यवस्था-व्यापी विश्लेषण पर शोध से पता चलता है कि सब्सिडी अपने उद्देश्य से आगे निकल गई है और अस्थिर हो गई है (शर्मा और गुलाटी 1995)।

**अमीर किसानों को सब्सिडी दी जाती है जबकि उन्हें सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए।**

कई निर्यात और शोधकर्ताओं (संत और दीक्षित 1996; होवेस और मुर्गई 2003; मोनारी और मोस्तेफई 2001) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे अमीर और गरीब दोनों किसानों के लिए समान सब्सिडी की उपलब्धता प्रतिकूल है। प्रत्यक्ष (इनपुट, उर्वरक, ऋण, बीमा) और अप्रत्यक्ष सब्सिडी (मूल्य समर्थन) सभी के लिए सुलभ हैं और प्रकृति में प्रतिगामी हैं, जिससे गरीबों की तुलना में धनी किसानों को अधिक लाभ होता है। ऋण माफी और कृषि पंपों जैसे कृषि उपकरणों की सब्सिडी की भी इसी आधार पर आलोचना की गई है।

### **मूल्य समर्थन और बजटीय भुगतान का शुद्ध प्रभाव नकारात्मक है।**

ऐसा लगता है कि सरकार ने किसानों को उदार सब्सिडी की पेशकश की है, लेकिन हो सकता है कि निर्यात पर प्रतिबंध, मूल्य विकृतियों और फसल की पसंद की विकृतियों ने किसानों को कोई लाभ पहुंचने नहीं दिया। 2001 में, शरद जोशी की अध्यक्षता में कृषि पर बने एक टास्क फोर्स ने पाया कि किसानों को विभिन्न सरकारी हस्तक्षेपों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच की सीमाओं के कारण 1980 से 2000 के बीच कम से कम 3,00,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ (जोशी 2015)। लेखक का दावा है कि 3,00,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा कम करके आंका गया है क्योंकि इसमें केवल कृषि उपज की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बीच का अंतर शामिल है और इसमें कृषि बाजारों के कामकाज में बहुत सारे सरकारी हस्तक्षेपों के वित्तीय परिणाम शामिल नहीं किए गए हैं।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के 2018 के एक अध्ययन में पाया गया कि ज़्यादातर देशों में कृषि उत्पादकों को समर्थन सकारात्मक है, भारत में यह विपरीत है क्योंकि सरकार अक्सर अंतरराष्ट्रीय कीमतों से नीचे फसलों के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करती है जिसकी वजह से कुल मिलाकर किसानों को नकारात्मक सब्सिडी मिलती है (आईसीडी 2018)। ओईसीडी के अध्ययन में कई वर्षों के लिए 19 प्रमुख फसलों की कीमत पर विचार किया और पाया गया कि किसानों को सालाना उन सभी के लिए नकारात्मक रूप से सब्सिडी दी गई थी। सकल कृषि प्राप्तियों के हिस्से के रूप में व्यक्त, 2000-02 में किसानों को समर्थन का औसत -3.5 प्रतिशत और 2014-16 में -6.2 प्रतिशत था (ओईसीडी 2018)। शुद्ध नकारात्मक प्रभाव बजटीय भुगतानों का एक संयोजन है, जो मुख्य रूप से इनपुट सब्सिडी और बाजार समर्थन मूल्य से बना है।

द इकोनॉमिस्ट के एक लेख (द इकोनॉमिस्ट 2018) में भी यह बताया गया कि कैसे भारत कृषि के लिए प्रत्यक्ष सहायता पर सालाना लगभग 30 अरब डॉलर खर्च करता है लेकिन किसानों को 40 अरब डॉलर से वंचित करता है। अंतर को फसलों के लिए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों में अंतर द्वारा समझाया गया है। इसके अलावा, अपनी आबादी के लिए कृषि उत्पादों की खपत वस्तुओं और अपने किसानों के लिए आय के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश के तहत देश उपभोक्ताओं को 25% कृषि आय हस्तांतरित करता है।

**कई रिपोर्टों से पता चलता है कि किसानों को सीधे हस्तांतरण से वर्तमान हस्तांतरण तंत्र से पैदा हुई कुछ चुनौतियों का समाधान हो जाएगा।**

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) एक नीतिगत हस्तक्षेप है जो वर्तमान सब्सिडी व्यवस्था से अधिक प्रभावी हो सकता है। कम रिसाव और कम बिचौलियों के साथ डीबीटी अधिक लागत प्रभावी हैं (बाथला, जोशी, कुमार, और अन्य 2020)। उर्वरक सब्सिडी को सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने से उर्वरकों के ज़रूरत से ज्यादा इस्तेमाल को रोका जा सकेगा और अन्य क्षेत्रों में यूरिया का अवैध रूप से विचलन बंद हो जाएगा। हालांकि, इसमें सफलता भूमि दस्तावेजों की गुणवत्ता और आधार कनेक्टिविटी की स्थिति पर टिकी पर है। (रामस्वामी 2019)

अशोक गुलाटी का तर्क है कि "मुफ्त बिजली का प्रावधान और भूजल का (अत्यधिक) दोहन एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और मिलकर फसल की पसंद तय करने में योगदान देते हैं" (गुलाटी, कपूर, और बाउटन 2019, पेज. 38)। एक सुधार, जो उनका सुझाव है कि भूजल के अवक्षेपण को कम करेगा, वह है मुफ्त बिजली की सुविधा को समाप्त करना और नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों की ओर बढ़ना। इससे रिसाव को रोकने और ग्रामीण आय असमानता को कम करने की संभावना है, क्योंकि इस समय बड़े किसानों को मौजूदा सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है (गुलाटी, कपूर, और बाउटन 2019)।

## तेलंगाना की ऋतु बंधु योजना

तेलंगाना में 2018 में शुरू हुई ऋतु बंधु योजना किसानों के लिए एक नकद हस्तांतरण योजना है। तेलंगाना सरकार सभी किसानों को प्रति सीजन प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये की राशि प्रदान करती है (चटर्जी, गुलाटी और हुसैन 2018)। इसके अधिक समावेशी और बेहतर पहुंच होने की भविष्यवाणी की गई थी। योजना के प्राप्तकर्ताओं पर किए गए 2020 के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 66% किसानों ने प्रत्यक्ष इनपुट सब्सिडी (रमेश 2020) पर नकद हस्तांतरण को प्राथमिकता दी। सीमांत भूमि वाले किसानों में यह वरीयता अधिक मजबूत थी, जिसमें 85% नकद हस्तांतरण को प्राथमिकता दे रहे थे। किसानों ने नकद हस्तांतरण को प्राथमिकता दी क्योंकि यह तत्काल कृषि जरूरतों को पूरा कर सकता था और सरकार द्वारा इनपुट सब्सिडी के माध्यम से प्रदान किए गए बीज और उर्वरक खराब गुणवत्ता के थे। नकद हस्तांतरण के साथ, किसान यह चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि वे कौन से बीज और उर्वरक खरीदेंगे (रमेश 2020)।

## 7. ऋण बाजारों में हस्तक्षेप करने की इच्छा से बचें

एनएफआईएस (2016)<sup>3</sup> के अनुसार ज्यादातर कृषि परिवारों ने पिछले साल फसल या पशुधन से संबंधित संकट की घटनाओं का सामना करने की बात कही। इस तरह की संकटपूर्ण घटनाओं से निपटने के लिए किसान संस्थागत और अनौपचारिक ऋण स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार मुख्य रूप से ब्याज दरों में सब्सिडी देकर और कृषि ऋण माफ करके ऋण बाजार में हस्तक्षेप करती है।

### अल्पकालिक ऋण बकाया कृषि ऋण पर हावी हैं।

भारत में खेती की विशेषता छोटी जोत से जुड़ी है। सीजन की शुरुआत में इनपुट पर खर्च करने के लिए अपर्याप्त आय और बचत किसानों को ऋण पर निर्भर होने के लिए प्रेरित करती है। इस कारण से, अल्पावधि ऋण - 6-12 महीने की - कृषि से संबंधित बकाया ऋणों पर हावी है। किसान इनका इस्तेमाल फसल के मौसम में खर्च के लिए करते हैं, न कि निश्चित पूंजी में निवेश करने के लिए। ऋण संस्थानों को सीधे हस्तांतरण के माध्यम से ऋणों पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे वे किसानों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अल्पकालिक ऋण में वृद्धि आर्थिक सहायता योजनाओं से प्रेरित होती है (रिजर्व बैंक 2019बी)।

<sup>3</sup> लगभग 54% परिवारों ने दी गई संदर्भ अवधि में कम से कम एक बार बारिश की अनियमितताओं के कारण फसल की विफलता का सामना करने की सूचना दी है, 28% ने कीटों के प्रकोप आदि के कारण समस्याओं का सामना किया है, और क्रमशः 18% और 10% किसान परिवारों ने बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव, और बाढ़ एवं बीमारियों आदि के कारण पशुओं की हानि के चलते समस्याओं का सामना किया।

## ब्याज दर में छूट छोटे और सीमांत किसानों के खिलाफ काम करती है।

भारतीय रिजर्व बैंक अनिवार्य करता है कि शुद्ध बैंक ऋण का कम से कम 40% हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की ओर निर्देशित किया जाए (रिजर्व बैंक 2018)। इसमें से 18% हिस्सा कृषि ऋण, कृषि ढांचे और सहायक गतिविधियाँ की ओर निर्देशित है। सरकार इस ऋण पर कुछ हद तक सब्सिडी देती है; आम तौर पर, समर्थन राशि लगभग दो प्रतिशत कम ब्याज दरों के बराबर होती है। शीघ्र पुनर्भुगतान के मामले में अतिरिक्त 3% की छूट है, ब्याज दर को घटाकर 4% कर दिया गया है (2019)।

किसानों को ऋण प्रदान करने की सरकार की कोशिशों के बावजूद, बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसानों को संस्थागत स्रोतों से कोई ऋण नहीं मिल पा रहा है।

जब सरकार ब्याज दर की सीमा तय करके या ब्याज दरों में सब्सिडी देकर कृषि ऋण बाजार में हस्तक्षेप करती है, तो यह उन किसानों को रोकती है जो औपचारिक संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए अधिक कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के शोध में पाया गया है कि औपचारिक संस्थान से उधार लेने वालों में से 40% लोग खुद को मजबूर महसूस करते हैं (राजीव और वानी 2019)। तरलता की कमी किसानों को, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने में निवेश करने से सीमित करती है। यह इस बात से स्पष्ट है कि कैसे बहुत छोटी भूमि (0.01 हेक्टेयर से कम आकार) वाले किसानों ने गैर-औपचारिक स्रोतों से 76 प्रतिशत ऋण प्राप्त किया (राजीव और वानी 2019)।

अखिल भारतीय स्तर पर, 26% कृषि ऋण गैर-संस्थागत स्रोतों से आते हैं। संस्थागत स्रोतों में से अधिकांश ऋण संपन्न किसानों को जाता है, न कि उन्हें जिन्हें ऋण की आवश्यकता होती है। 83% बड़े किसान केवल 60% सीमांत किसानों के विपरीत संस्थागत ऋणों पर निर्भर थे (राजीव और वानी 2019)। भूमि दस्तावेजों और काशतकारी अनुबंधों के अभाव में, गहने पर लिए जाने वाले ऋण तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि औपचारिक संस्थान छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने से कतराते हैं।

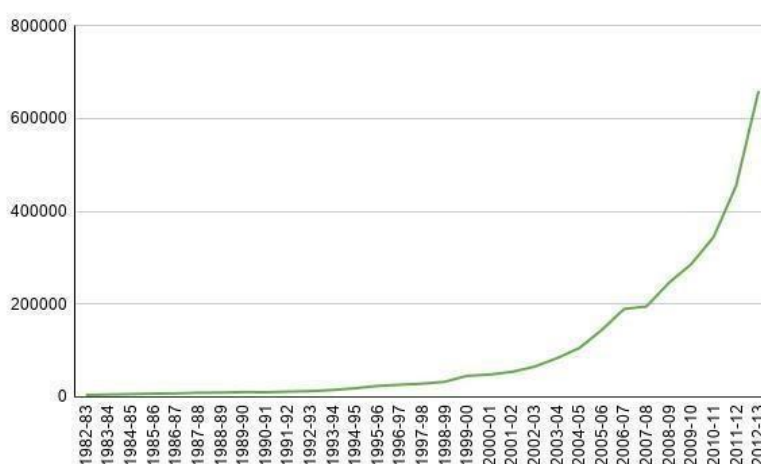
## कर्ज माफ करने का चलन निवेश या उत्पादकता को नहीं, बल्कि ऋण वापसी में चूक को बढ़ावा देता है।

हाल के वर्षों में, भारत में चुनाव के समय के आसपास कर्ज माफ करने की संस्कृति का फिर से उदय दिखा है, यह चलन 1990 के दशक में कम हो गया था। इस प्रथा के समर्थकों का तर्क है कि किसानों को अक्सर "कर्ज की अधिकता" का सामना करना पड़ता है, जहाँ किसी भी अतिरिक्त आय, उधार या अर्जित, का ऋण चुकाने में निवेश किया जाता है। इस तरह के बकाया ऋणों की माफी किसानों को इस जाल से मुक्त करती है। कई शोधकर्ताओं ने इस परिकल्पना के सत्यापन के लिए गहराई से समीक्षा की।

2008 में, सरकार ने चार करोड़ परिवारों के लिए एक व्यापक कर्जमाफी की पेशकश की। यह राशि जीडीपी का 1% और कर राजस्व का 8% थी। दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को पूर्ण राहत मिली और 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को आंशिक राहत मिली। इस अंतर ने शोधकर्ताओं को एक प्रतितथ्यात्मक होने की अनुमति दी। उम्मीद यह थी कि कर्ज की माफी किसानों को औपचारिक संस्थानों से उधार लेने और उत्पादक निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित और सक्षम करेगी। लेकिन इस तरह के एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन का भी कृषि उत्पादकता या निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा (केंज 2016)। अनौपचारिक उधारी का हिस्सा बढ़ा; खासकर उनमें ज़्यादा बढ़ा जिन्हें पूर्ण राहत मिली। इससे भी बदतर यह था कि जिन लोगों ने पूर्ण सहायता प्राप्त की, वे ऋण वापसी में चूक के प्रभावों के बारे में कम परेशान थे। इससे इस बात की पुष्टि होता है कि "विवेकपूर्ण उधार और पुनर्भुगतान की संस्कृति को खत्म किए बिना ऋण माफ करना" मुश्किल है।

2008 के ऋण माफी के नुकसानदेह प्रभाव उसके बाद के वर्षों में सामने आते रहे। योजना के उच्च जोखिम वाले जिलों में नए ऋणों का अनुपात कम हो गया और अच्छे ऋण इतिहास वाले लोगों में ऋण वापसी में चूक बढ़ गई। इसके अलावा, ऋण माफी का आर्थिक गतिविधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा (जिन और केंज 2017)। इसी तरह, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऋण वसूली प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले 2010 के एक अध्यादेश के कारण चूक में वृद्धि हुई और किसानों को ऋण उपलब्धता में गिरावट आई।

इसके अलावा, संस्थागत ऋण तभी स्थिर होता है जब ऋणदाता कर्जदारों का खाका बनाने, पुनर्भुगतान का पूर्वानुमान लगाने और उधार लागतों की भरपाई करने में सक्षम हों। रियायती ऋण और ऋण माफी कार्यक्रम इन तीनों को शामिल नहीं करता है। पिछले कुछ वर्षों में, बैंकर स्वाभाविक रूप से छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने से कतरा रहे हैं। इस समस्या को हल करने के लिए, सरकार ने एक और अस्थायी समाधान लागू किया है। 2015 से, बैंकों के लिए अपने ऋण पोर्टफोलियो का 8% छोटे किसानों के लिए निर्धारित करना अनिवार्य कर दिया गया है।



चित्र 12: कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए कुल संस्थागत ऋण (करोड़ रुपए में)

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक 2019ए

**ऋण राहत का कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए।**

मुखर्जी, सुब्रमण्यम और तांत्री (2018) ने पाया कि 2008 की ऋण माफी में संकट ग्रस्त किसानों के-जिन्होंने बीमा दावा दायर किया और प्राप्त किया- गैर-संकटग्रस्त किसानों की तुलना में कार्यक्रम के बाद ऋण वापसी में चूकने की संभावना कम थी। लेखकों का तर्क है कि ऋण राहत केवल संकटग्रस्त किसानों की मदद करती है, उदाहरण के लिए, जो बाहरी झटके से प्रभावित होते हैं। अन्यथा, यह रणनीतिक चूक को बढ़ावा देता है, ऋण बाजार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 सुझाव देता है कि "ऋण माफी सबसे अच्छी स्थिति में एक आपातकालीन दवा हो सकती है जो दुर्लभ मामलों में पूरी तरह से निदान और बीमारी की पहचान के बाद दी जा सकती है, यह कोई मुख्य आहार नहीं हो सकती।"

यह देखते हुए कि ब्याज दर सब्सिडी मुख्य रूप से प्रचुर भूमि वाले किसानों को लाभान्वित करती है, ब्याज सहायता योजना को हटाकर उसकी जगह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को दी जानी चाहिए। इससे सरकार को सभी किसानों को सर्वव्यापक छूट देने के

बजाय, चुनिंदा किसानों को सब्सिडी लक्षित करने में मदद करेगी (द इंडियनएक्सप्रेस2019)। इनके अलावा, भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि किसान आसानी से ऋण प्राप्त कर सकें।

## 8. कृषि-प्रौद्योगिकी के परीक्षण, बिक्री और इस्तेमाल को विनियमित करने के लिए एकल-विंडो मंच स्थापित करना

कृषि में प्रौद्योगिकी के परीक्षण और इस्तेमाल करने की मंजूरी देने में अस्थिरता और अंतरविभागीय समन्वय की कमी से ऐसे निर्णयों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे के मूल्यांकन की जरूरत का पता चलता है। इस खंड में, हम ऐसी विसंगतियों के दो उदाहरणों पर प्रकाश डालेंगे: पहला, आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों के इस्तेमाल पर बहस और दूसरा, वह हालिया आदेश जिसमें 27 कीटनाशकों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।

**भारत में जीएम बीजों का इस्तेमाल विवादों से भरा हुआ है।**

बीजों के आनुवंशिक संशोधन से रसायनों, कीटों या पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रतिरोध जैसे वांछनीय लक्षण सामने आते हैं। संशोधन क्रॉस-निषेचन द्वारा नहीं बल्कि बीज के डीएनए में वांछनीय जीन को शामिल करके किया जाता है। किसी ने इसके पक्ष में तो किसी ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए, 2016 में पश्चिम बंगाल में जीएम सरसों की खेती के खिलाफ एक सविनय अवज्ञा आंदोलन – सरसों सत्याग्रह - का आयोजन किया गया था (सहगल 2019)। इसके अलावा, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में किसानों ने इसके कानूनी निहितार्थों की जानकारी के बावजूद जीएम बीज लगाकर इसका विरोध किया है।

**देश भर के किसानों ने उन जीएम फसलों की खेती की है जिनके लिए मंजूरी नहीं मिली है।**

महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में अवैध जीएम (एचटी) कपास उगाया जाता है। 2019 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में, सरकार ने पुलिस द्वारा इन राज्यों में 67 मामलों की जांच करने और 102 लाख रुपये से ज्यादा के अवैध कपास के बीज को जब्त किए जाने की जानकारी दी थी (सहगल 2019)। जीएम के समर्थक दो कारणों से प्रयोग करने के लिए उत्सुक हैं: पहला, भारतीय और वैश्विक फसल उत्पादन के बीच तकनीकी अंतर को पाटने के लिए, और दूसरा, क्योंकि इससे किसानों को फसल उत्पादन की कुल लागत को कम करने में मदद मिलती है (बेरा2019)।

जीएम खेती के खिलाफ कार्यकर्ताओं का तर्क है कि कानूनी रूप देने से पहले जीएम बीजों के व्यापक उपयोग की वजह से प्रतिबंध लागू करना मुश्किल हो जाता है, जो अंततः इसके नियामक अनुमोदन का मार्ग प्रशस्त करता है (बेरा2019)। उदाहरण के लिए, गुजरात में, 2010 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधीनस्थ वैधानिक इकाई जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी), जो जीएम बीजों की मंजूरी के लिए जिम्मेदार है, ने सरकार को अवैध रूप से उगाई गयी बीटी कपास को जलाने का आदेश दिया था। हालांकि, सरकार ने इसका पालन करने से इनकार कर दिया क्योंकि बीटी कपास का पहले ही व्यापक इस्तेमाल किया जा चुका था।

**मंजूरी जारी करने में राजनीतिक प्रभाव का भी हाथ है।**

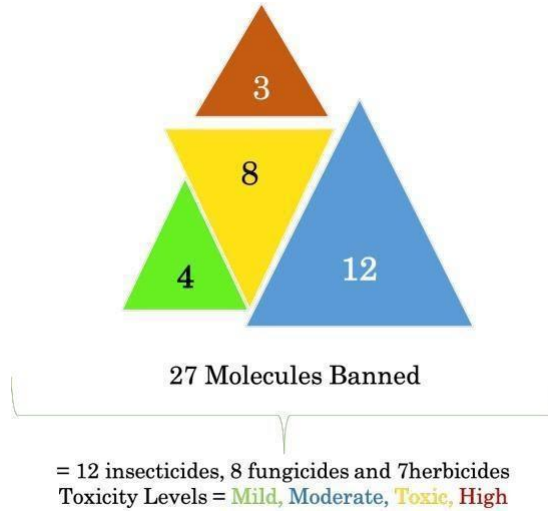
प्रत्येक जीएम किस्म के अलग-अलग उपयोग और प्रभाव होते हैं और उन्हें जाँच और परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। नियामक निर्णय राजनीतिक विचारों से दृढ़ता से प्रभावित हुए हैं न कि वैज्ञानिक निष्कर्षों से। मंत्री अक्सर जीईएसी के प्रस्तावों की अनदेखी करते हैं; 2010 में, जीईएसी ने बीटी बैंगन की खेती को मंजूरी दे दी, लेकिन तत्कालीन पर्यावरण मंत्री ने "अनिश्चितकालीन रोक" लगा दी क्योंकि पूरे राज्य/देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इसी तरह जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती की मंजूरी वापस ले ली गई (बेरा2019)। एक और उदाहरण यह है कि कैसे जीईएसी ने हाल ही में राज्यों को निःशुल्क परीक्षण करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने की ज़रूरत की शुरुआत की थी क्योंकि कृषि राज्य का विषय है और यह राज्यों को एक निश्चित स्तर की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। जीईएसी की मंजूरी के बाद भी राज्यों ने अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने से मना कर दिया। जीईएसी और राज्यों के बीच इस तरह के संघर्ष प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए एक सुचारू नियामक ढांचे के निर्माण में बाधा डालते हैं (शुक्ला और अन्य 2018)।

**सरकार की अनिर्णय की स्थिति का असर किसानों, और प्रौद्योगिकी का विकास करने वालों पर पड़ता है।**

कई जीएम प्रौद्योगिकियां अपने विकास के अंतिम चरण में हैं, और वैज्ञानिक नीति में बदलाव और बढ़ते व्यावसायीकरण के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं। जहाँ कई सरकारी संस्थान जैसे जीईएसी, ईगमोरिस (इंडियन जीएमओ रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम), बायोसेप्टी हाउस आदि बेहतर नियामक ढांचे के लिए जैव सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, उनकी नीतियां एक-दूसरे से टकराती हैं जिससे भ्रम और अव्यवस्था पैदा होती है। उदाहरण के तौर पर ट्रांसजेनिक सरसों को मंजूरी देने पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। डीएचएम-11 को 2017 में जीईएसी से मंजूरी मिल गई, लेकिन तत्कालीन पर्यावरण मंत्री ने इसे पुनर्विचार के लिए जीईएसी के पास वापस भेज दिया। जीईएसी ने इस सरसों का विकास करने वाले को और अधिक फील्ड परीक्षण करने का आदेश दिया, यह फील्ड परीक्षणों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देने में राज्यों की आनाकानी की वजह से हुआ (बेरा2019)।

**कीटनाशकों के इस्तेमाल पर भी सरकार का रूख अनिर्णय की स्थिति वाला है।**

मई 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव के आदेश का मसौदा जारी किया था। प्रतिबंध लागू होने पर, इन कीटनाशकों के इस्तेमाल, विनिर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण, आयात पर रोक लग जाता (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2020ए)। अचानक से उठाए गए इस कदम को किसानों, उद्योग और यहाँ तक कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय (एमसीएफ) सहित सभी हितधारकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को लिखे एक पत्र में, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव ने तर्क दिया कि सूचीबद्ध कीटनाशकों में भारत के घरेलू कीटनाशक उद्योग का 40% शामिल है। उन्होंने बताया कि उसमें सूचीबद्ध सभी कीटनाशक केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबी और आरसी) में पंजीकृत थे और उसकी शर्तों को पूरा करते थे (द इंडियन एक्सप्रेस 2020)।



चित्र 13: 2020 उर्वरक अणुओं पर प्रतिबंध

कई लोगों ने इसके इस्तेमाल किए गए सबूतों की गुणवत्ता के आदेश और कानून के न होने की आलोचना की है। यह प्रतिबंध 2013 की अनुपम वर्मा समिति की सिफारिशों पर आधारित है। समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। निर्णय पर पहुंचने के लिए हितधारकों के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया। इसके अलावा, मंत्रालय ने पहले टिप्पणियों के लिए 45 दिनों की अनुमति दी और फिर इसे तीन महीने (पांडे 2020) तक बढ़ा दिया, फिर से, छह जुलाई को, मंत्रालय ने केरल सरकार की सिफारिशों के आधार पर ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। इस बार मंत्रालय ने टिप्पणियों के लिए 30 दिनों की मंजूरी दी और आखिरकार इसे 60 दिनों तक बढ़ा दिया। हितधारकों ने फिर से प्रतिबंधों की आलोचना की।

कीटनाशकों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध के चलते, आदेश ने इन कीटनाशकों के निर्यात पर भी रोक लगा दी होती। हालांकि, कीटनाशक उद्योग के प्रतिनिधित्व के बाद, एक वेबिनार में, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उल्लेख किया कि मंत्रालय मामला दर मामला आधार पर इन कीटनाशकों के निर्यात की अनुमति देगा (लाइवमिंट 2020)।

इस तरह का मनमाना निर्णय लेना कृषि-प्रौद्योगिकी के नियमन में एक चुनौती बना हुआ है। अचानक से लगाए जाने वाले प्रतिबंध का उन लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो पहले से ही किसी विशेष वस्तु में निवेश कर चुके हैं, यह निजी कंपनियों को हतोत्साहित करते हैं, और उपयोगकर्ताओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। मीडिया की खबरों में बताया गया है कि कैसे कुछ प्रतिबंधित कीटनाशकों के विकल्प के अभाव में, उनकी बिक्री में वृद्धि हुई है जबकि आदेश पूरे विश्वास के साथ कहता है कि विकल्प मौजूद है।

**एकल मंच की व्यवस्था से कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है।**

एक स्पष्ट नियामक ढांचे के लिए, एक एकल मंच होना ज़रूरी है, जिससे सभी निजी और सार्वजनिक कंपनियां पंजीकरण कर सकें, नियामक जानकारी प्राप्त कर सकें और मंजूरी हासिल कर सकें। ये मंजूरी साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए और कोई भी प्राधिकरण, बिना उचित कारण या उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर उन्हें अचानक से निरस्त न करे।



भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2013 में आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी (एमएसटी2013) के जीवों और उत्पादों के नियमन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण- भारतीय जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण (बीआरएआई) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। विधेयक 2013 में पेश किया गया था और स्थायी समिति के पास भेजा गया था। विधेयक को संशोधन के साथ फिर से पेश किए जाने की संभावना है - हालांकि, समयसीमा को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। स्थापना के बाद, यह अनुसंधान, परिवहन, आयात, नियंत्रण, पर्यावरण पर प्रभाव, विनिर्माण और इस तरह के सभी उत्पादों के इस्तेमाल से संबंधित विषयों के लिए एक एकल मंच का निर्माण करने में सफल होगा (शुक्ला और अन्य 2018)। स्वतंत्र प्राधिकरण जैव प्रौद्योगिकी के नियमन तक सीमित नहीं हो सकता है, लेकिन कीटनाशकों के इस्तेमाल सहित सभी कृषि-प्रौद्योगिकी की अनदेखी कर सकता है।

नियामक कानून के अन्य क्षेत्रों में, जहां भारत एक स्पष्ट नियामक ढांचा स्थापित करने में धीमा रहा है, भारत अन्य देशों के सम्मानित नियामक निकायों के साक्ष्य पर सहजता से भरोसा करता रहा है। उदाहरण के लिए, नव आषधि और क्लिनिकल ट्रायल नियम 2019 दवा की मंजूरी के मामले में ऐसा करता है। भारत स्थानीय क्लिनिकल ट्रायल के लिए छूट प्रदान करता है अगर दवा को किसी अनुमोदित देश में एक नियामक निकाय से मंजूरी मिल गई है (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2019)। ऐसा कोई कारण नहीं है कि जैव प्रौद्योगिकी के मामले में ऐसी नीति नहीं चुनी जा सकती।

## 4. निष्कर्ष: अन्नदाता से कृषि उद्यमी

कोविड-19 के प्रसार से भारत में कृषि आपूर्ति श्रृंखला के तहत-नहस होने का खतरा पैदा हो गया है। राज्य की मंडियों के एकाधिकार और इसके बाहर बिक्री चैनलों की अनुपस्थिति ने एक शून्य पैदा कर दिया जिसने कृषि सुधारों को न केवल आवश्यक बल्कि बेहद जरूरी बना दिया। मई 2020 के पहले दो हफ्तों के भीतर, हमने देखा कि तीन राज्य- मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश- किसानों को एपीएमसी मंडियों के बाहर बेचने की अनुमति दे रहे थे (हक 2020)।

केंद्र सरकार ने भी संकट का इस्तेमाल दीर्घकालिक मुद्दों को ठीक करने के लिए लक्षित लंबित सुधारों को पेश करने के एक अवसर के रूप में किया। केंद्र सरकार ने तीन ऐतिहासिक अध्यादेश पारित किए। ये तीनों कृषि में शासन के सुधार से संबंधित हैं।

1. सबसे पहले, उन्होंने 65 साल पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) 1955 में संशोधन किया। आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कृषि उत्पादों पर भंडारण की सीमा लगाने की सरकार के अधिकार को खत्म करता है जब तक कि युद्ध, अकाल, आपदा जैसी "असाधारण" परिस्थितियां या एक असाधारण मूल्य वृद्धि की स्थिति न हो। संसाधक या मूल्य श्रृंखला प्रदाताओं को इस सीमा से छूट दी गई है। कई लोगों ने "असाधारण" मूल्य वृद्धि की परिभाषा को लेकर चिंता व्यक्त की है, जैसे - बागवानी उत्पादों के खुदरा मूल्य में 100% वृद्धि; और खराब न होने वाले कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि। हमारी राय में सरकार को एक कदम और आगे बढ़ते हुए संसद के अगले सत्र में आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त कर देना चाहिए। ऐसे में जब हम प्रचुरता और समृद्धि के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, वस्तुओं की कमी को ध्यान में रखकर बनाए गए एक अधिनियम की अब कोई जगह नहीं है।

2. दूसरा अध्यादेश, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा अध्यादेश), 2020, किसान द्वारा किए जाने वाले "पहले लेनदेन" के मिथक को तोड़ने की दिशा में उठाया गया एक विवेकपूर्ण कदम है। यह पैन कार्ड रखने वाले लोगों और

सहकारी समितियों को सीधे किसान से खरीदने की अनुमति देता है, जिससे राज्यों के बाहर और अंतरराज्यीय वाणिज्य खुल जाता है।

3. अंत में, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता, 2020 किसानों को कम से कम एक सीजन और अधिकतम पांच साल के लिए कंपनियों के साथ अनुबंध करने की अनुमति देता है, यह उन फसलों के लिए बढ़ाया जा सकता है जिनका उत्पादन चक्र पाँच साल से ज़्यादा लंबा है। अध्यादेश पार्टियों को कीमत सहित आपसी सहमति वाले नियम और शर्तें निर्धारित करने की अनुमति देता है। हालांकि कीमत एमएसपी से कम हो सकती है या नहीं इस पर कुछ नहीं कहा गया है। अधिनियम का शीर्षक हालांकि अब भी संरक्षणवाद और पितृत्ववाद के पक्षपात को दर्शाता है। बाजार वाली अर्थव्यवस्था में कीमत का कोई आश्वासन नहीं होता है। बार-बार यह खेल खेलने वाले लाखों खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा कीमतों की खोज की जाती है। जहाँ तक सरकार एक बड़ी खरीदार है, उन्हें इस खेल में शामिल होने और बाजार मूल्य पर अनाज खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ मौसमों में, इससे सरकारी धन की बचत होगी, कुछ मौसमों में विक्रेताओं को एक बोनस मिलेगा।

हालांकि कृषि भंडारण और विपणन कानूनों में ये बदलाव ज़रूरी हैं, फिर भी हमें यह देखना बाकी है कि ये जमीन पर कैसे काम करते हैं। बिहार को एपीएमसी अधिनियम को निरस्त किए 13 साल हो चुके हैं, लेकिन बाजारों का घनत्व अब भी कम है। इस विषय पर परस्पर विरोधी मत हैं। 'बिजनेस इनसाइडर' को दिए एक साक्षात्कार में अशोक गुलाटी (कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष) ने कहा, "निजी क्षेत्र आगे आएगा और इससे लड़ेगा" (गिल 2020)। इसके उलट, एनसीईईआर की एक रिपोर्ट सरकार के लिए कर रियायतों को पेश करने और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने एवं मजबूत करने के उपाय करने का तर्क देती है (कन्नन और पोहित 2019)।

जहाँ हम कृषि अर्थव्यवस्था की गड़बड़ियों को ठीक करते हैं, हमारे लिए किसान को खेती का काम छोड़ने में सक्षम बनाना और इसके बाहर लाभदायक अवसर पैदा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने बार-बार तर्क दिया है कि सबसे अच्छा सुधार किसानों को खेती से बाहर निकालना है ताकि उद्योग के लिए एक सस्ता श्रम बल प्रदान किया जा सके। इसमें कोई शक नहीं है कि औद्योगिक दृष्टिकोण संभावनाओं से भरा होना चाहिए ताकि वह कृषि से बाहर जाने वाली श्रम शक्ति को अवशोषित कर सके। हालांकि प्राथमिक क्षेत्र में सुधार के एक पूर्व शर्त के रूप में, नौकरियों के सृजन के लिए माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों की राह देखना मूर्खता होगी।

## संदर्भ ग्रंथ सूची

- Aggarwal, Nidhi, Sargam Jain, and Sudha Narayanan. 2016. "The long road to transformation of agricultural markets in India: Lessons from Karnataka." WP-2016-026, *Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR)*, <https://cutt.ly/Nd1OQ8u>.
- Aggarwal, Nidhi, Sargam Jain, and Susan Thomas. 2014. "Do futures markets help in price discovery and risk management for commodities in India?" WP-2014-020, *Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR)*, <https://cutt.ly/1d2fWCU>.
- Amritanshu. 2017. "India's Agricultural Pricing Policy: Intervention and Repercussion." *Indian National Interest* (December 14, 2017). <https://cutt.ly/Ud1U3Le>.
- Arora, VPS. 2013. "Agricultural Policies in India: Retrospect and Prospect." Vol. 26(2) pp. 135-157, *Agricultural Economics Research Review*, <https://cutt.ly/Ad9i8Yn>.
- Bathla, Seema, Pramod Kumar Joshi, Anjani Kumar, et al. 2020. "Agricultural Growth and Rural Poverty Reduction in India." *India Studies in Business and Economics Series*, <https://cutt.ly/vd2Jqhb>.
- Bera, Sayantan. 2019. "Inside India's genetic crop battlefield." *Live Mint*, <https://cutt.ly/Ld1PfMC>.
- Bhardwaj, Mayank, and Rajendra Jadhav. 2018. "India raises winter crop prices ahead of 2019 elections." *Reuters World News* (October 3, 2018). <https://cutt.ly/Qd1IcVV>.
- Bhat, Shripad, Shaikh Mouzam, K Naveena, and Murtuza Khan. 2015. "Impact of Delisting on Prices and Arrivals of Vegetables." Vol. 6 pp. 628-631, *Research Journal of Agricultural Sciences*, <https://cutt.ly/Md2H5te>.
- Bhayani, Rajesh, and Dilip Jha. 2014. "FAQ on the Essential Commodities Act." *Business Standard* (July 8, 2014). <https://cutt.ly/Kd1O9ys>.
- Bhoi, Binod, Sujata Kundu, Vimal Kishore, and D. Suganthi. 2019. "Supply Chain Dynamics and Food Inflation in India." *RBI Bulletin: October 2019*, <https://cutt.ly/nd1PWKD>.
- Burman, Anirudh, Ila Patnaik, Shubho Roy, and Ajay Shah. 2018. "Diagnosing and overcoming sustained food price volatility: Enabling a National Market for Food." Working Paper 236, *National Institute for Public Finance and Policy*, <https://cutt.ly/ud2GNEC>.
- Chand, Ramesh. 2018. "Innovative policy interventions for transformation of farm sector." In *26th Annual Conference of Agricultural Economics Research Association (India)*. <https://cutt.ly/ld1PTg8>.
- Chand, Ramesh, and Jaspal Singh. 2016. "Study Report on Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reforms Across Indian States and UTs." *NITI Aayog*, <https://cutt.ly/wd8MVOX>.
- Chatterjee, Tirtha, Ashok Gulati, and Siraj Hussain. 2018. "Supporting Indian farmers: Price support or direct income/investment support?" Working Paper No 357, *Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER)*, <https://cutt.ly/Ed2F023>.
- Chatterjee, Tirtha, Raghav Raghunathan, and Ashok Gulati. 2019. "Linking farmers to futures market in India." Working Paper 383, *Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER)*, <https://cutt.ly/Zd1OOZI>.
- Chikermane, Gautam. 2018. *70 Policies That Shaped India: 1947 to 2017, Independence to \$2.5 Trillion*. 25–27. Observer Research Foundation. <https://cutt.ly/ld2Dofu>.
- CSDS-Lokniti. 2018. "State of Indian Farmers." *Centre for Study of Developing Societies*, <https://cutt.ly/5d1UBzf>.
- Dalwai, Ashok. 2017. *Report of the Inter-Ministerial Committee on Doubling Farmers' Income: Volumes I-XIV*. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India. <https://cutt.ly/Ed22Qh1>.
- Dave, Sandeep, and Hiral Motta. 2017. "Using Agricultural Lands for Non-Agricultural Purposes in Maharashtra: Important 2016 Amendments." *Cyril Amarchand Mangaldas Blog*, accessed July 28, 2020. <https://cutt.ly/cd1IN09>.
- From Annadata to Farmpreneur: Playbook for Reforming Indian Agriculture | 27

- Deshpande, Tanvi. 2017. "State of Agriculture in India." Analytical Reports, *PRS Legislative Research*, <https://cutt.ly/Fd1Y9HL>.
- Dey, Kushankur, Vasant P. Gandhi, and Kanish Debnath. 2019. "Farmers' Participation in India's Futures Markets: Potential, Experience, and Constraints." *Indian Institute of Management, Ahmedabad*, <https://cutt.ly/cd1OJBw>.
- Financial Express. 1998. "Commodity futures markets: An interview with Dr Ajay Shah," February 16, 1998. <https://cutt.ly/cd1OYdt>.
- Food and Agricultural Organisation. 2005. "Towards an Indian Common Market: Removal of Restrictions on Internal Trade in Agriculture Commodities." Submitted to National Commission on Farmers, Government of India, <https://cutt.ly/jd1O8lr>.
- . 2019. "India at a glance." Accessed May 5, 2020. <https://cutt.ly/Vd1PFGH>.
- Ghatak, Maitreesh, and Sanchari Roy. 2007. "Land Reform and Agricultural Productivity in India: A Review of the Evidence." Vol. 23(2) pp. 251-269, *Oxford Review of Economic Policy*, <https://cutt.ly/Sd2Dh8R>.
- Ghosh, Soumya Kanti. 2018. "India's potential economic growth is a lot lower than expected." *The Print* (December 1, 2018). <https://cutt.ly/Jd1PEDb>.
- Gill, Prabhjote. 2020. "'I have been asking for this for 20 years,' says Ashok Gulati, agriculture scientist, cheering the changes to Essential Commodities Act and APMC." *Business Insider* (May 16, 2020). <https://cutt.ly/Fd1PIW8>.
- Giné, Xavier, and Martin Kanz. 2017. "The Economic Effects of a Borrower Bailout: Evidence from an Emerging Market." Vol. 31(5) pp.1752-1783, *The Review of Financial Studies*, <https://cutt.ly/Vd2HMju>.
- Government of Andhra Pradesh. 1974. "The Andhra Pradesh Land Reforms (Ceiling on Agricultural Holdings) Rules." <https://cutt.ly/Td1PcAq>.
- Government of Rajasthan. 1973. "The Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holding Act." <https://cutt.ly/ed1Pbew>.
- Grossman, Nick, and Dylan Carlson. 2011. "Agriculture Policy in India: The Role of Input Subsidies." USITC Executive Briefings on Trade, *United States International Trade Commission*, <https://cutt.ly/Md1PtX3>.
- Gulati, Ashok. 2020. "Offloading excess foodgrain stocks through open market operations will generate much-needed resources for govt." *The Indian Express* (June 22, 2020). <https://cutt.ly/bd1Cw3a>.
- Gulati, Ashok, and Pritha Banerjee. 2015. "Rationalising Fertiliser Subsidy in India: Key issues and policy options." Working Paper 307, *Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER)*, <https://cutt.ly/Ld28Vcy>.
- Gulati, Ashok, Tirtha Chatterjee, and Siraj Hussain. 2017. "Agricultural Commodity Futures: Searching for Potential Winners." Working Paper No. 349, *Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER)*, <https://cutt.ly/md1OZrc>.
- Gulati, Ashok, Devesh Kapur, and M Bouton. 2019. "Reforming Indian Agriculture." Working Paper, *Center for the Advanced Study of India (CASI) and ICRIER*, <https://cutt.ly/hd2zPnP>.
- Gulati, Ashok, and Shweta Saini. 2015. "Leakages from public distribution system (PDS) and the way forward." Working Paper No. 294, *Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER)*, <https://cutt.ly/vd9r8Am>.
- Hanstad, Tim, Robin Neilsen, and Jennifer Brown. 2004. "Land and Livelihoods Making Land Rights Real for India's Rural Poor." LSP Working Paper 12, *Food and Agriculture Organisation*, <https://cutt.ly/Ud1IOEx>.
- Haq, Zia. 2020. "MP, UP and Gujarat end state monopoly on agri markets." *Hindustan Times* (May 15, 2020). <https://cutt.ly/nd1PhRt>.
- Hassan, Nusrat. 2016. "Agricultural law in India: Overview." *Thomson Reuters Practical Law*, accessed May 5, 2020. <https://cutt.ly/sd1JxT>.
- Howes, Stephen, and Rinku Murgai. 2003. "Karnataka: Incidence of agricultural power subsidies." Vol. 38 (16), *Economic & Political Weekly*, <https://cutt.ly/Ld2vvL5>.

- IDFC Foundation. 2013. "India Rural Development Report 2012-13," <https://cutt.ly/md9tIpa>.
- International Trade Administration, US Commerce Department. 2020. "India Country Commercial Guide." Accessed July 31, 2020. <https://cutt.ly/Yd82w0u>.
- Jha, Dilip Kumar. 2016. "APMC delisting: Vegetables price crash as farmers sell directly to consumers." *Business Standard* (August 3, 2016). <https://cutt.ly/ud1Ov9L>.
- Joshi, Sharad. 2015. "We Need A Marshall Plan For Indian Agriculture." *Swarajya: Read India Right* (May 5, 2015). <https://cutt.ly/ed1U0J2>.
- Kannan, Elumalai, and Sanjib Pohit. 2019. "Identifying Binding Constraints to Agricultural Growth in Bihar." Policy Brief No. 3 — 2019, *National Council for Applied Economic Research (NCAER)*, <https://cutt.ly/5d1PzD4>.
- Kanz, Martin. 2016. "What Does Debt Relief Do for Development? Evidence from India's Bailout for Rural Households." Vol. 8(4) pp. 66-99, *American Economic Journal: Applied Economics*, <https://cutt.ly/Vd2HBPr>.
- Kumar, Parmod. 2016. "Price Differences in Wholesale Prices, Retail Prices and Price Realised By Farmers For Onion and Grapes in Karnataka." Research Report - ADRTC/168, *Agricultural Development and Rural Transformation Centre, Institute for Social and Economic Change*, <https://cutt.ly/Ad2zQrx>.
- Lipton, Michael. 1975. "Urban Bias and Food Policy in Poor Countries." ISSN: 0306-9192, *Food Policy*, <https://cutt.ly/td2uMZB>.
- LiveMint. 2020. "Govt to permit exports of banned pesticides on case to case basis: Narendra Singh Tomar." *Live Mint*, <https://cutt.ly/jd5IXrf>.
- Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. 2015. *Cost of Cultivation & Related Data*. Government of India. <https://cutt.ly/Fd1PNK6>.
- . 2017. "Model APLM Act." <https://cutt.ly/Td1PCaz>.
- . 2019a. *Agriculture Census 2015-16 (Phase I): All India Report on Number and Area of Operational Holdings*. Government of India. <https://cutt.ly/kd20iiE>.
- . 2019b. "Categorisation of Farmers," February 5, 2019. Accessed May 7, 2020. <https://cutt.ly/hd1UIXc>.
- . 2020a. "Draft Banning of Insecticides Order: 2076 GI/2020." <https://cutt.ly/ud11YZ1>.
- . 2020b. "Farmer Portal: Minimum Support Prices." <https://cutt.ly/Wd1PIWw>.
- . 2020c. "Second Advance Estimates of Production of Foodgrains 2019-2020," February 18, 2020. Accessed May 7, 2020. <https://cutt.ly/Zd1Uela>.
- Ministry of Chemicals and Fertilizers. 2020. "Study of System of Fertilizer Subsidy." Presented on 17 March 2020 to the Lok Sabha Standing Committee, *Government of India*, <https://cutt.ly/Nd22HbK>.
- Ministry of Commerce and Industry. 2019. "Agriculture Export Policy." <https://cutt.ly/rd1OgEO>.
- . 2020. *Index Files For WPI Series*. Government of India. <https://cutt.ly/Md29Nvc>.
- Ministry of Finance. 2014. *Economic Survey of India 2013-14*. Government of India. <https://cutt.ly/cd04Njv>.
- . 2016. *Economic Survey of India 2015-16*. Government of India. <https://cutt.ly/cd04Njv>.
- . 2018. *Economic Survey of India 2017-18*. Government of India. <https://cutt.ly/xd1UOW3>.
- . 2019. "Interest Free Loans to Farmers," July 15, 2019. Accessed May 5, 2020. <https://cutt.ly/Bd1PHlz>.
- . 2020. *Economic Survey of India 2019-20*. Government of India. <https://cutt.ly/ed1Y55S>.
- Ministry of Health and Family Welfare. 2019. "New Drugs and Clinical Trial Rules." <https://cutt.ly/8d2V5CV>.
- Ministry of Science and Technology. 2013. "The Biotechnology Regulatory Authority of India Bill."

<https://cutt.ly/Wd1PglG>.

- Ministry of Statistics and Programme Implementation. 1992. *All India Debt & Investment Survey*. Government of India. <https://cutt.ly/Md2K7P5>.
- . 2003. *All India Debt & Investment Survey*. Government of India. <https://cutt.ly/xd2Ly2l>.
- . 2013. *All India Debt & Investment Survey*. Government of India. <https://cutt.ly/Jd2LqNm>.
- . 2017. *Statistical Year Book India*. Government of India. <https://cutt.ly/Ad2LsLC>.
- . 2018. *Energy Statistics*. Government of India. <https://cutt.ly/Qd2Lit2>.
- Mishra, Prabhudatta. 2019. "APMC reforms: Some headway made; inter-state trade distant goal." *Financial Express* (December 16, 2019). <https://cutt.ly/pd1OmCA>.
- Mishra, Prachee, and Roopal Suhag. 2017. "Land Records and Titles in India." Analytical Reports Series, *PRS Legislative Research*, <https://cutt.ly/Hd1OeZ3>.
- Mitra, Barun. 2018. "Free the Farmers." *Pragati* (April 6, 2018). <https://cutt.ly/Od1U7fb>.
- Monari, L, and D Mostefai. 2001. "India: Power supply to agriculture, Volume 1: Summary Report." Report No. 22171-IN, *Energy Sector Unit, South Asia Regional Office, The World Bank*, <https://cutt.ly/qd23EzC>.
- Mukherjee, Debashish, Himanshu Bajaj, Namit Garg, and Joshua Abraham. 2013. "Feeding a billion: Role of the Food Processing Industry." *AT Kearney and FICCI*, <https://cutt.ly/8d9tHah>.
- Mukherjee, Saptarshi, Krishnamurthy Subramanian, and Prasanna Tantri. 2018. "Borrowers' distress and debt relief: Evidence from a natural experiment." Vol. 61(4) pp. 607–635, *The Journal of Law and Economics*.
- National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). 2018a. *All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17*. <https://cutt.ly/ld2MEsg>.
- . 2018b. *Status of Marketing Infrastructure under Electronic National Agriculture Markets - A Quick Study*. <https://cutt.ly/Nd2MiLG>.
- NITI Aayog. 2016. *Report of the Expert Committee on Land Leasing*. NITI Aayog, Government of India. <https://cutt.ly/xd11Xw1>.
- . 2017. *India Three Year Action Agenda: 2017-20*. Government of India. <https://cutt.ly/md1O6yd>.
- OECD. 2018. *Agricultural Policies in India*. OECD Food and Agricultural Reviews. OECD Publishing, Paris. <https://cutt.ly/Bd24CeA>.
- . 2020. "Statistics on Agricultural Output: Crop production Indicator." Accessed August 1, 2020. <https://cutt.ly/Nd9rmgP>.
- Outlook India. 2011. "Uttarakhand HC Strikes Down Land Ceiling Law" (September 23, 2011). <https://cutt.ly/Rd9aOzi>.
- Pal, Sarmistha, Prabal Roy Chowdhury, and Zoya Saher. 2019. "Unintended Consequences of Land Ceiling Legislations and Land Acquisition-Theory and Evidence from the Indian States." Available at SSRN 3271982, <https://cutt.ly/Od9tiql>.
- Palaniappan Shanmugam, Velmurugan, and Mohammad Irshad VK. 2017. "Role of Commodity Futures on Indian Agricultural Commodity Market," <https://cutt.ly/Gd1OlgQ>.
- Pandey, Samyak. 2020. "Move to ban 27 pesticides will hand over Rs 12,000-cr market to China: Indian manufacturers." *The Print* (June 10, 2020). <https://cutt.ly/id12bM8>.
- Rajeev, Meenakshi, and B.P Vani. 2019. *Interest Subvention for Short-term Crop Loans in Karnataka*. Reserve Bank of India, Institute for Social, and Economic Change. <https://cutt.ly/cd2NBGH>.
- Ramaswami, Bharat. 2019. "Agricultural Subsidies: Study Prepared for XV Finance Commission (Final Report)." *Indian Statistical Institute*, <https://cutt.ly/yd1Pe6b>.
- Ramesh, Padmini. 2020. "Cash Transfers as a Policy Instrument in Agriculture: Study of the Rythu Bandhu Scheme and the Land Record Updation Programme in Telangana." PhD diss., Tata Institute of Social Sciences.

- Reserve Bank of India. 2018. *Frequently Asked Questions: Priority Sector Lending - Targets and Classification*. <https://cutt.ly/Dd2N4VV>.
- . 2019a. *Direct Institutional Credit for Agriculture and Allied Activities - Total (Short-Term and Long-Term)*. <https://cutt.ly/qd6QtUf>.
- . 2019b. *Report of Internal Working Group to Review Agricultural Credit*. <https://cutt.ly/Vd2Nw96>.
- Saini, Shweta, and Marta Kozicka. 2014. "Evolution and Critique of Buffer Stocking Policy of India." Working Paper 283, *Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER)*, <https://cutt.ly/Ud1OBRg>.
- Sant, Girish, and Shantanu Dixit. 1996. "Beneficiaries of IPS subsidy and impact of tariff hike." Vol. 31(51), *Economic & Political Weekly*, <https://cutt.ly/dd2vkDR>.
- Sehgal, Rashme. 2019. "GM Crop Regulation: Government Continues to Remains Lackadaisical." *News Click* (July 4, 2019). <https://cutt.ly/od1Pdlr>.
- Sharma, Anil, and Ashok Gulati. 1995. "Subsidy Syndrome in Indian Agriculture." Vol. 30(39), *Economic & Political Weekly*, <https://cutt.ly/9d1PySv>.
- Sharma, Yogima. 2017. "Remove agriculture from Essential Commodities Act: Niti Aayog." *The Economic Times* (August 28, 2017). <https://cutt.ly/Pd1li7p>.
- Shukla, Manish, Khair Tuwair Al-Busaidi, Mala Trivedi, and Rajesh K. Tiwari. 2018. "Status of research, regulations and challenges for genetically modified crops in India." Vol. 9(4) pp. 173-188, *GM Crops & Food: Biotechnology in Agriculture and the Food Chain*, <https://cutt.ly/xd2H1OW>.
- Srikant, Dr. M. 2017. "Swachh Bharat Mission: How close are we to the finish-line?" *Pragati* (October 1, 2017). <https://cutt.ly/Hd1UWuh>.
- Suryawanshi, Sudhir. 2019. "Maharashtra: Change in law opens unlimited land for state developers." *DNA India* (February 27, 2019). <https://cutt.ly/Bd1I1WS>.
- The Economist. 2018. "India's government claims to subsidise farmers, but actually hurts them." *Asia Edition* (July 12, 2018). <https://cutt.ly/Rd1UMCV>.
- The Hindu Business Line. 2018. "Model land leasing Act yet to find many takers: NITI Aayog" (November 23, 2018). <https://cutt.ly/md1I5PB>.
- . 2019. "Indian commodity futures market can learn a lot from China" (August 8, 2019). <https://cutt.ly/rd1OXLP>.
- The Indian Express. 2019. "Replace interest subvention scheme with Direct Benefit Transfer, avoid loan waivers: RBI panel" (September 14, 2019). <https://cutt.ly/Ld1Pavq>.
- . 2020. "Abrupt ban on pesticides sparks row between ministries" (June 12, 2020). <https://cutt.ly/rd11FNZ>.
- The Telegraph. 2019. "Scrapping the Essential Commodities Act may do little to increase investments." *Online Edition* (June 21, 2019). <https://cutt.ly/td1leDn>.
- The World Bank. 2020. "World Development Indicators." Accessed July 15, 2020. <https://cutt.ly/Wd23DUc>.
- Thompson, Phillip. 2019. *The International Trade Barrier Index 2019*. Property Rights Alliance. <https://cutt.ly/vd9b0Ty>.



## सेंटर फॉर सिविल सोसायटी

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी (सीसीएस) दिल्ली स्थित एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है जो सार्वजनिक नीति के माध्यम से सामाजिक बदलाव को आगे बढ़ाता है। शिक्षा, आजीविका, शासन और नीति प्रशिक्षण से जुड़ा हमारा काम सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में पसंद और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। नीति को व्यवहार का रूप देने के लिए, हम अनुसंधान, पायलट परियोजनाओं और वकालत के माध्यम से नीति नियंत्रणों और विचारकों के साथ काम करते हैं। पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी के थिंक टैंक और सिविल सोसाइटीज प्रोग्राम की ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट 2018 में हमें शीर्ष 100 थिंक टैंक में जगह दी गयी है।

सीसीएस एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहाँ हर इंसान व्यक्तिगत, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी पसंद का जीवन व्यतीत करे और हर संस्थान जवाबदेह हो।



## एटलस नेटवर्क

एटलस नेटवर्क एक गैर-लाभकारी संगठन है जो 90 से ज्यादा देशों में 475 से अधिक मुक्त-बाजार संगठनों के वैश्विक नेटवर्क को स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी विचारों और संसाधनों से जोड़ता है।





## सेंटर फोर सिविल सोसाइटी

ए-69 हौजखास  
नई दिल्ली 110016  
फ़ोन- +91 11 2653 7456  
वेबसाइट- [WWW.CCS.IN](http://WWW.CCS.IN)